घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 274- मंगलवार 04- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

उपचुनाव रिजल्ट से विपक्ष को नई उम्मीद

प्रशांत किशोर के आगे कैसे फीकी पड़ी बांकीपुर की लड़ाई?

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने भाजपा प्रत्याशी को 19,324 मतों से हराया

पटना,03 अगस्त 2026। बिहार की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 मतों के अंतर से पराजित किया। इस जीत के साथ प्रशांत किशोर ने सक्रिय चुनावी राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। अंतिम परिणाम के अनुसार, प्रशांत किशोर को कुल 64,151 मत प्राप्त हुए। भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 44,827 मत मिले,जबकि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की उम्मीदवार रेखा गुप्ता 14,273 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। इसके अलावा 646 मतदाताओं

ने 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प चुना। चुनाव परिणाम घोषित होते ही जन सुराज के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। विभिन्न स्थानों पर समर्थकों ने मिठाइयां बांटी, एक-दूसरे को बधाई दी और जीत का जश्न मनाया। सोमवार सुबह शुरू हुई मतगणना के शुरुआती दौर से ही प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए थे। मतगणना के प्रत्येक चरण के साथ उनकी बढ़त लगातार बढ़ती गई और अंत तक कायम रही। भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के अनुसार, मतगणना कुल 32 चरणों में संपन्न हुई और सभी चरणों में प्रशांत किशोर अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे रहे।

सरकारों को अब शिक्षा,रोज़गार और विकास जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा : प्रशांत किशोर

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने केंद्र और बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने इस चुनाव के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि अब राजनीति केवल जाति, नारे और सत्ता तक सीमित नहीं रह सकती। सरकारों को शिक्षा,रोजगार और विकास जैसे बुनियादी मुद्दों पर गंभीरता से काम करना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में भी जनता इसी तरह का फैसला सुनाएगी। मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम केवल एक सीट की जीत नहीं, बल्कि जनता की सोच में आए बदलाव का संकेत है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 30 वर्ष का गढ़ 30 दिनों में ढह गया। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, पढ़ाई और रोजगार का काम करे। अगर ऐसा नहीं करेगी तो आगे भी यही हाल होगा। उन्होंने बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को राज्य का नेतृत्व सौंपकर बिहार का विकास संभव नहीं है। उनका कहना था कि बिहार की जनता अब सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपेक्षा कर रही है कि राज्य को ऐसा मुख्यमंत्री मिले, जो ईमानदार, योग्य और दूरदर्शी हो तथा शिक्षा, रोजगार और समग्र विकास के लिए स्पष्ट विजन के साथ काम करे। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो समर्थन और विश्वास मिला है, उसे वह अपनी जिम्मेदारी मानते हैं।

दतिया उपचुनाव : कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,016 मतों से हराया

मध्य प्रदेश की चर्चित दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना संपन्न हुई। इस उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हरा दिया है। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 66,757 (42.39 फीसदी) वोट प्राप्त हुए और जीत हासिल की,जबकि भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 60,741 (38.57 फीसदी) वोट हासिल किए। वहीं,तीसरे स्थान पर रहे आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के दामोदर यादव मण्डल को 22,527 वोट प्राप्त किए। इसके अलावा धर्मेन्द्र सिंह पंवार (राइट टु रिकॉल पार्टी)-957 वोट,जितेन्द्र माझी (आपका गणतंत्र पार्टी)-927,रामसिंह कुशवाह (राष्ट्रीय समानता दल)-324, बालकिशुन विश्वकर्मा (परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया)-204,शुभम राजपूत(भारतीय सभ्यता पार्टी)-163, डॉ. राखी वाला (राष्ट्रीय समाधान जनमोर्चा)-144, संजना सिंह किन्नर (भारतीय गण वार्ता पार्टी) - 141 और हरदास कुशवाहा (भीम सेना) को 112 वोट मिले। इनके अलावा निर्दलीयों में राघवेन्द्र सिंह-727, बाबूलाल सोनी-691, देवेश परिहार निमोना- 642, रोहित गुप्ता, 585, ब्रजेन्द्र शाह (बापा साहब)-384, वेद भैया-219, सुरेश अहिरवार- 219, एडवोकेट हँसमुखी लोधी- 204, धर्मेन्द्र सिंह- 196, कन्छेदीलाल कुशवाहा-179 और नोटा को 455 मत हासिल हुए। दतिया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे मतगणना प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा और निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया। मतगणना शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हुई। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति सामने नहीं आई। उन्होंने सभी मतदान कर्मियों, सुरक्षा बलों और संबंधित विभागों के सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया।

गुजरात की मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत सतीश पटेल 30,499 मतों से विजयी

गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शानदार जीत दर्ज की है। भाजपा उम्मीदवार सतीश पटेल ने कांग्रेस के भीखा रबारी को 30,499 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया। भाजपा उम्मीदवार सतीश पटेल ने जीत के बाद कहा कि मांजलपुर की जनता ने जिस प्रकार स्वर्गीय योगेश पटेल (योगेश काका) को अपना स्नेह और समर्थन दिया था, उसी प्रकार उन्हें भी भरपूर आशीर्वाद और विश्वास दिया है। उन्होंने इस जीत का श्रेय मांजलपुर की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। कांग्रेस उम्मीदवार भीखा रबारी ने अपनी हार स्वीकार करते हुए आरोप लगाया कि मतदान के अंतिम चरण में भाजपा की ओर से भय का माहौल बनाया गया, जिसका चुनाव परिणाम पर प्रभाव पड़ा। उल्लेखनीय है कि मांजलपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चुनाव में 37.05 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। सोमवार को 19 राउंड की मतगणना के बाद भाजपा उम्मीदवार सतीश पटेल को विजयी घोषित किया गया। इस जीत के साथ भाजपा ने मांजलपुर विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा और स्वर्गीय योगेश पटेल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में सफलता हासिल की।

सोडियम नाइट्रेट से घुटा दम...

एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत,सुसाइड नोट से खुला राज

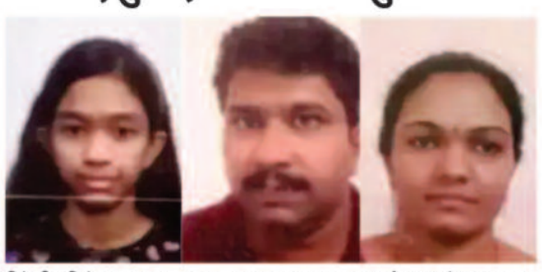

पिंपरी-चिंचवड़,03 अगस्त 2026। महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मोरवाड़ी स्थित करिश्मा ग्लोरी सोसाइटी में परिवार के मुखिया विनोद पिल्ले (50), उनकी पत्नी सिरजा पिल्ले (45) और बेटी पूर्णिमा पिल्ले (19) की मौत हुई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे कथित तौर पर आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, विनोद पिल्ले का शव उनके घर से बरामद हुआ था, जबकि उनकी पत्नी और बेटी गंभीर हालत में मिली थीं। दोनों को तत्काल वाईसीएम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही संत तुकाराम नगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को घर से एक पत्र भी मिला है, जिसे विनोद पिल्ले द्वारा लिखा हुआ बताया जा रहा है। इसमें कथित तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराने की बात कही गई है। पुलिस पत्र समेत घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि परिवार की मौत किसी जहरीले पदार्थ के संपर्क में आने से हुई हो सकती है। पुलिस सोडियम को घर से नाइट्रेट का एक कंटेनर मिला है। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। मामले में पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद में हंगामा....

लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पास,राज्यसभा में MSME संशोधन बिल को मंजूरी

नई दिल्ली,03 अगस्त 2026। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित कर गई है। इसके पहले लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या (सीजेआई सहित) 34 से बढ़ाकर 38 करने संबंधी बिल बिना चर्चा के पास कर दिया। वहीं राज्यसभा ने सूक्ष्म विकास (संशोधन) बिल पास कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार तक स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसदों ने प्रश्नकाल शुरू होते ही नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के सदन आने और उनके बयान की मांग करते हुए नारे लगाए। संसद के मौजूदा सत्र में 8 बिल लिस्ट किए गए हैं। इनमें से वंदे

मातरम और पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल (पेपर लीक) दोनों सदनों में पास हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन बिल लोकसभा में और MSME विकास (संशोधन) बिल राज्यसभा में पास हुआ है। जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल, आयकर (संशोधन) बिल,, विदेशी अंशदान संशोधन बिल और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल को संसद की मंजूरी मिलनी बाकी है। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से वैधानिक प्रस्ताव पर बोलने का आग्रह किया, लेकिन नारेबाजी जारी रहने के कारण बिल को वोटिंग के लिए रखा गया और फिर पास कर दिया गया। विपक्ष के सदस्यों ने अध्यादेश लाने के खिलाफ एक वैधानिक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे वॉइस वोट से खारिज कर दिया गया। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि राम मंदिर दान का मुद्दा सोमवार को भी संसद में उठाया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि राम मंदिर ट्रस्ट संत-महात्माओं को क्यों नहीं सौंपा जाता? विश्व हिंदू परिषद के सदस्य ट्रस्ट में क्यों हैं? उन्होंने कहा कि महपाल सिंह के एसआईटी के सामने दिए गए बयान से मामला और उजागर हुआ है। उनके मुताबिक, दान की रकम पर कारसेवकपुरम में रहने वाले विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों के पास गई।

ई20 पेट्रोल पर सरकार के जवाब से नए सवाल खड़े हुए : जयराम रमेश

नई दिल्ली,03 अगस्त 2026। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने ई20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि 29 जुलाई को संसद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दिए गए जवाब से जितने सवालों के उत्तर मिले, उससे कहीं अधिक नए सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर ई20 को पूरी तरह सुरक्षित बता रही है, जबकि दूसरी ओर उपभोक्ताओं के अनुभव और विभिन्न तकनीकी दस्तावेज कई अहम चिंताएं सामने रखते हैं। जयराम रमेश ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नितिन गडकरी ने संसद में कहा था कि ई20 ईंधन को वर्षों के वैज्ञानिक

परीक्षण के बाद लागू किया गया है और इससे वाहनों को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचने का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन पिछले कई महीनों से देशभर के वाहन मालिक और मैकेनिक माइलेज में कमी, इंजन के प्रदर्शन में गिरावट, 2023 से पहले बने वाहनों की ई20 के साथ अनुकूलता, कोल्ड-स्टार्ट की समस्या,इंजन के तेजी से घिसने,फ्यूल इंजेक्टर जाम होने,फ्यूल लाइन में जंग लगने तथा रबर के पुर्जों में दरार आने जैसी शिकायतें लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जून 2026 में 2023 से पहले बने पेट्रोल वाहनों के 44 हजार से अधिक मालिकों पर किए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में लोगों ने ई20 लागू होने के बाद अपने वाहनों पर प्रतिकूल प्रभाव महसूस होने की बात कही है।

महिला पहलवान यौन शोषण केस में बृजभूषण सिंह बरी...बोले- होइहि सोइ जो राम रचि राखा

नई दिल्ली,03 अगस्त 2026। भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। सोमवार को फैसले के वक्त पूर्व सांसद बृजभूषण और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर कोर्ट में मौजूद रहे। फैसले के बाद बृजभूषण ने कहा- जज ने कहा कि बृजभूषण और विनोद तोमर आप लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। मैंने पहले कहा था कि अगर कोई आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मेरे लिए खुशी का दिन है। होइहि सोइ जो राम रचि राखा। कोर्ट के फैसले के बाद पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कहा- हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे। यौन शोषण का यह मामला जनवरी 2023 में सामने आया था।

विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया था। बृजभूषण तब डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट थे। आरोप था कि नाबालिग समेत 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ शिकायत की थी, इसमें एक नाबालिग थी। लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अप्रैल 2023 में एफआईआर दर्ज की गई। बाद में नाबालिग पहलवान ने शिकायत वापस ले ली थी। 2 जुलाई, 2026 को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में कुल 1133 दिनों में 127 सुनवाई हुई। 32 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

संपादकीय

न्याय की राह में सबसे बड़ा अपराध...
अपराध को छिपाने की कोशिश

बलात्कार और विशेषकर नाबालिग से दुष्कर्म जैसे अपराध केवल किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होते,बल्कि पूरे समाज के नैतिक विवेक को चुनौती देते हैं। ऐसे मामलों में यदि अपराध सिद्ध होता है तो दोषी को कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन उतना ही गंभीर प्रश्न तब खड़ा होता है,जब अपराध के बाद उसे दबाने,समझौता कराने या साक्ष्यों को प्रभावित करने के प्रयास के आरोप सामने आते हैं।

अम्बिकापुर में सामने आए नाबालिग आदिवासी बालिका से कथित दुष्कर्म के मामले में अब चर्चा केवल मुख्य आरोपी तक सीमित नहीं रह गई है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि घटना के अगले ही दिन एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार कराया गया,जिसमें ₹8 लाख को पुराना उधार दर्शाया गया। यदि यह दस्तावेज़ वास्तव में केवल आर्थिक लेन-देन का रिकॉर्ड है,तो जांच इसे स्पष्ट कर देगी। लेकिन यदि जांच में यह सामने आता है कि इसका उद्देश्य अपराध को दबाना,पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाना या आरोपी को कानूनी लाभ पहुँचाना था,तो यह स्वयं एक गंभीर आपराधिक कृत्य हो सकता है।

यहीं से पुलिस की असली परीक्षा शुरू होती है...

कानून केवल अपराध करने वाले को दंडित करने के लिए नहीं बना है, बल्कि उन लोगों तक भी पहुँचने के लिए बना है जो अपराध को छिपाने, साक्ष्य मिटाने, गवाहों को प्रभावित करने या पीड़ित को समझौते के लिए मजबूर करने का प्रयास करते हैं। यदि किसी भी स्तर पर ऐसे प्रयास हुए हैं,तो उनकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

इस प्रकरण का दूसरा और अधिक चिंताजनक पक्ष आदिवासी एवं ग्रामीण समाज का कानून पर घटता विश्वास है। यदि कोई पिता यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि समाज साथ देगा तभी वह थाने जाएगा,तो यह केवल उसकी व्यक्तिगत विवशता नहीं बल्कि व्यवस्था के प्रति अविश्वास का संकेत है। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ नहीं कही जा सकती।

साथ ही यह भी उतना ही आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को केवल सोशल मीडिया अभियानों या जनभावनाओं के आधार पर दोषी घोषित न किया जाए। भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि दोष सिद्ध होने तक प्रत्येक आरोपी निर्दोष माना जाता है। इसलिए अंतिम निर्णय न्यायालय का ही होगा। लेकिन इस सिद्धांत का अर्थ यह भी नहीं कि जांच केवल सतही स्तर पर पूरी कर दी जाए। यदि कथित दस्तावेज़,गवाहों के बयान और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य किसी व्यापक साजिश की ओर संकेत करते हैं,तो विवेचना वहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए जहाँ सबसे अधिक शोर सुनाई दे रहा है। जांच का उद्देश्य सत्य तक पहुँचना होना चाहिए,चाहे वह किसी भी व्यक्ति,पद,प्रभाव या आर्थिक शक्ति तक क्यों न ले जाए।

इस पूरे प्रकरण में एक और प्रश्न समाज से भी जुड़ा है। क्या हम ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार के साथ खड़े होते हैं,या फिर रसूख,जाति, पैसे और प्रभाव के आधार पर अपनी चुप्पी चुन लेते हैं? अपराधियों का सबसे बड़ा संरक्षण उनकी ताकत नहीं,बल्कि समाज की खामोशी होती है।

अब निगाहें पुलिस विवेचना पर हैं। यदि जांच निष्पक्ष, वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित हुई, तो सच स्वयं सामने आ जाएगा। लेकिन यदि किसी भी स्तर पर प्रभाव,दबाव या पक्षपात दिखाई देता है, तो न्याय व्यवस्था पर जनता का विश्वास और कमजोर होगा।

इसलिए यह मामला केवल एक एफआईआर या एक आरोपी का नहीं है। यह कानून के शासन,पुलिस की निष्पक्षता और समाज की संवेदनशीलता–तीनों की परीक्षा है।

न्याय तभी पूर्ण माना जाएगा जब दोषी कोई भी हो–मुख्य आरोपी हो या अपराध को छिपाने वाला–कानून सबके लिए समान रूप से लागू होता हुआ दिखाई दे।

वैश्विक द्वंद्व के उपहार,पेट्रोल डीजल और गैस की अनियंत्रित महंगाई

संजीव ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

विश्व अर्थव्यवस्था की धमनियों में यदि किसी तत्व को रक्त की उपमा दी जाए तो वह निस्संदेह तेल है। विश्व के सभी देशों में भारत सहित पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ा दिए गए हैं इनमें सबसे कम भारत में ही पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ाए गए हैं। यह थोड़ी राहत की बात हो सकती है परंतु भारत की जैसी अर्थव्यवस्था पर निश्चित तौर पर यह बढ़े हुए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आम जनता पर भारी पड़ सकते हैं। भारत में आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने का प्रभाव आम जनता पर हमेशा उनकी जेब पर भारी कटौती किए जाने का अंदेशा रहता है। भारत एक विकासशील देश है और यहां की अर्थव्यवस्था बहुत ही संवेदनशील एवं परिवर्तनशील है भारत की जनसंख्या वैश्विक देश में अग्रणी मानी जाती है देश में यदि थोड़े से भी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तो इस पर देश की अर्थव्यवस्था पर भारी परिवर्तन परिलक्षित होता है। पेट्रोलियम पदार्थ केवल वाहनों का ईंधन भर नहीं हैं, बल्कि आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की गति, उत्पादन, परिवहन, ऊर्जा और व्यापार की आधारशिला हैं। जब तेल की कीमतों में असंतुलित वृद्धि होती है तो उसका प्रभाव केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि खेतों की मिट्टी से लेकर कारखानों की मशीनों और आम आदमी की रसोई तक महसूस किया जाता है। आज वैश्विक स्तर पर बढ़ती पेट्रोल-डीजल कीमतों ने भारत सहित अनेक देशों की आर्थिक संरचना को झकझोर कर रख दिया है।

रूस-यूक्रेन युद्ध,पश्चिम एशिया में तनाव, ओपेक देशों की उत्पादन नीतियां तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने कच्चे तेल की कीमतों को अस्थिर बना दिया। एक समय जो कच्चा तेल 60 से 70 डॉलर प्रति बैरल के बीच उपलब्ध था, वह कई अवसरों पर 100 डॉलर से ऊपर पहुंच गया। इसका सीधा प्रभाव उन देशों पर पड़ा जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर हैं। भारत अपनी कुल पेट्रोलियम आवश्यकता का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का अर्थ है–देश के आयात बिल में भारी वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव और व्यापार घाटे का विस्तार।

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि ने परिवहन लागत को तेजी से बढ़ाया। ट्रकों के भाड़े बढ़े तो फल, सब्जी,अनाज,दूध और दैनिक उपयोग की वस्तुएं महंगी हो गईं। किसान के लिए डीजल केवल वाहन चलाने का साधन नहीं,बल्कि सिंचाई और कृषि उपकरणों की शक्ति है। डीजल महंगा होने का अर्थ है खेती की लागत बढ़ना। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्पादन महंगा हुआ और महंगाई की दर लगातार ऊपर जाने लगी। आम नागरिक की आय स्थिर रही लेकिन खर्चों में वृद्धि होती गई। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए घरेलू बजट संतुलित करना कठिन हो गया।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने एक बार कहा था कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतें विकासशील देशों के लिए दोहरी चुनौती हैं–एक ओर महंगाई बढ़ती है और दूसरी ओर विकास की गति धीमी पड़ती है।

वास्तव में यही स्थिति आज अनेक देशों में दिखाई देती है। बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ गई। छोटे और मध्यम उद्योग,जो पहले ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा और मंदी से जूझ रहे थे, अब ऊर्जा लागत के दबाव में कमजोर पड़ने लगे हैं। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं ने भी चेतावनी दी है कि ऊर्जा संकट वैश्विक आर्थिक मंदी को और गहरा कर सकता है। जब परिवहन और उत्पादन महंगा होता है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। उपभोक्ता कम खरीदारी करते हैं,बाजार की मांग घटती है और उद्योगों का विस्तार रुकने लगता है। यही कारण है कि कई देशों में आर्थिक विकास दर अनुमान से कम रही। यूरोप में गैस और तेल संकट ने ऊर्जा आधारित उद्योगों को प्रभावित किया, जबकि एशियाई देशों में आयात लागत ने आर्थिक संतुलन बिगाड़ा। अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने कहा था कि यदि उत्पादन और परिवहन महंगे हो जाएं तो बाजार की आत्मा कमजोर पड़ जाती है। आज यह कथन बिल्कुल सटीक प्रतीत होता है। पेट्रोल-डीजल की कीमतें केवल व्यक्तिगत वाहन उपयोग को प्रभावित नहीं करतीं,बल्कि रेल, विमानन,शिपिंग और सार्वजनिक परिवहन की लागत को भी बढ़ाती हैं। विमान कंपनियों ने किराए बढ़ाए,मालवाहक कंपनियों ने अतिरिक्त शुल्क लगाए और इसका भार अंततः उपभोक्ता पर पड़ा।

भारत सरकार ने समय-समय पर उत्पाद शुल्क में कटौती और राज्यों द्वारा वैट कम करने जैसे कदम उठाए,लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता ने राहत को सीमित रखा। दूसरी ओर सरकारों के सामने भी चुनौती थी क्योंकि ईंधन पर मिलने वाला कर राजस्व विकास योजनाओं और आधारभूत संरचना निर्माण का महत्वपूर्ण स्रोत है। यदि कर घटाए जाते हैं तो सरकारी आय प्रभावित होती है,और यदि कीमतें बढ़ती हैं तो जनता पर बोझ पड़ता है। यह एक जटिल आर्थिक संतुलन बन गया है। ऊर्जा संकट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि केवल पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए विश्व अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत ने सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मंचों पर ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भारत के भविष्य की आवश्यकता बताया है। उनका मानना है कि यदि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है तो ऊर्जा के क्षेत्र में आयात निर्भरता कम करनी होगी।

हालांकि केवल नीतियां बना देने से समस्या समाप्त नहीं होगी। आवश्यक है कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जाए,ऊर्जा संरक्षण को जनआंदोलन बनाया जाए और वैकल्पिक ऊर्जा तकनीकों को सस्ता व सुलभ बनाया जाए। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तेल उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच संतुलित संवाद आवश्यक है,ताकि बाजार में कृत्रिम अस्थिरता कम हो सके।

अंततः यह कहा जा सकता है कि तेल की बढ़ती धार ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा कर दिया है। महंगाई,उत्पादन लागत, बेरोजगारी,व्यापार घाटा और आर्थिक असंतुलन जैसी समस्याएं इसी ऊर्जा संकट की परछाई बनकर उभरी हैं। यदि विश्व को स्थिर और संतुलित आर्थिक विकास की ओर बढ़ना है तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों,संतुलित नीतियों और वैश्विक सहयोग को प्राथमिकता देनी होगी। अन्यथा पेट्रोल-डीजल की यह बढ़ती आग केवल इंजन ही नहीं, अर्थव्यवस्था की पूरी संरचना को धीरे-धीरे झुलसाती रहेगी।

नकली धर्मगुरुओं के खिलाफ कार्रवाई करना क्यों आवश्यक है?

सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

भारत को हमेशा से संतों, ऋषियों और आध्यात्मिक ज्ञान की भूमि के रूप में जाना जाता रहा है। सदियों से पवित्र पुरुष और महिलाएं दूसरों को करुणा,सत्य,आत्म-अनुशासन और सेवा के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। विभिन्न सुधारकों और संतों के सिद्धांतों ने भारतीय समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किया है और लोगों को अज्ञानता,अंधविश्वास और सामाजिक बाधाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया है। लाखों भारतीयों के जीवन में आस्था का सर्वोपरि स्थान है,क्योंकि यही पवित्रता परम वास्तविकता है।

लेकिन देश में ऐसे लोगों का उदय हुआ है जो अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं,जिन्हें धर्मगुरु का उपनाम दिया गया है। वे धन, प्रभाव और निर्विवाद सत्ता के साम्राज्य स्थापित करने के लिए तथाकथित आध्यात्मिक भाषा को बढ़ावा देते हैं। भारत में कई मामलों में ऐसी महिलाओं पर यौन शोषण,संपत्ति मालिक को धोखा देना,अवैध भूमि अधिग्रहण, धमकी आदि जैसे गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया है या उन्हें दोषी ठहराया गया है। इससे न केवल ये प्रथाएं अवैध हो जाती हैं,बल्कि धार्मिक रूप से आध्यात्मिक प्रथाओं का पालन करने वालों की प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है।

इसीलिए,किसी भी अधिकारी द्वारा धर्म को आपराधिक कृत्यों की आड़ में इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उठाया गया कोई भी कदम न्याय और कानून के शासन का हिस्सा माना जाना चाहिए, न कि किसी के धर्म पर अत्याचार। संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी नागरिक कानून से ऊपर नहीं होता। गलत कामों की कोई खुली छूट नहीं होनी चाहिए और किसी को भी उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर कानून से छूट नहीं मिलनी चाहिए।

भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धार्मिक आस्था,धार्मिक रीति-रिवाजों और उनके प्रचार-प्रसार के अधिकार को एक विशेषाधिकार के रूप में मान्यता देता है। यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की अन्य संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सीमाओं के अधीन भी है। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन धार्मिक आड़ में वास्तविक धार्मिक गतिविधियों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल करने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए,सरकार द्वारा अधिकांश अनधिकृत आध्यात्मिक नेताओं, स्व-घोषित या आध्यात्मिक नेताओं की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने,उनकी गतिविधियों में वित्तीय अनियमितताओं या अन्य गैरकानूनी आचरण के मामलों की जांच करना,सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है,न कि धार्मिक आस्था में हस्तक्षेप।

धर्म का शोषण,पाखंडी धर्मगुरुओं द्वारा लोगों के लिए उत्पन्न किए जाने वाले सबसे बड़े खतरों में से एक है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त,भावनात्मक या मानसिक तनाव से जूझ रहे,या आर्थिक तंगी से परेशान लोग,बिना किसी संदेह के ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व के संपर्क में आ जाते हैं जो चमत्कारिक इलाज,अचानक धन-दौलत और जीवन की समस्याओं का चमत्कारिक,अलौकिक समाधान देने का वादा करता है। इस शोषण के कारण पीड़ितों और उनके परिवारों को आर्थिक नुकसान,मानसिक तनाव या इससे भी बदतर,जीवन भर कष्ट भोगना पड़ सकता है।

दुर्भाग्य से,अंधविश्वास फैलाने वाले ही एकमात्र लोग नहीं हैं। बल्कि यह समाज की भी ज़िम्मेदारी है जो पूछताछ करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने की अनिच्छा को बढ़ावा देता है। आस्था तर्क के विरुद्ध नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता विनम्रता, सहानुभूति और आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा देती है, जबकि बिना सोचे-समझे आज्ञा पालन आलोचना त्मक चिंतन को दबा देता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की समस्या यह है कि उसे ऐसे नागरिकों की आवश्यकता होती है जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन और हेरफेर के मामले में विवेकशील हों।

आधुनिक तकनीक के कारण यह और भी मुश्किल हो गया है। आजकल, एक स्वघोषित धर्मगुरु सोशल मीडिया पर लाखों अनुयायियों का समर्थन हासिल कर लेता है,जो सोच-समझकर गढ़ी गई कहानियों,भावनात्मक हेरफेर और बेतुके दावों के जाल में फंस जाते हैं। बहुत से लोग लोकप्रियता को विश्वसनीयता के बराबर मानते हैं। वीडियो, प्रशंसापत्र और सनसनीखेज सामग्री बिना किसी प्रमाण या गवाही के लोगों को ईश्वरीय होने का भ्रम पैदा कर सकती है। इसलिए,नागरिकों को मूर्ख बनने से बचाने के लिए पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। मीडिया पर भारी जिम्मेदारी है। पिछले कुछ वर्षों में खोजी पत्रकारिता ने स्वघोषित आध्यात्मिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के कई चर्चित मामलों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही,मीडिया संस्थानों को निष्पक्ष,संतुलित और भावुकता से रहित खबरें प्रस्तुत करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। जब पत्रकारिता अटकलों के बजाय सबूतों पर आधारित होती है,तो इससे जनता का विश्वास और भी मजबूत होता है।

पुलिस को भी निष्पक्ष और तटस्थ होना चाहिए। सभी आरोपों की जांच होनी चाहिए और प्रत्येक आरोपी को कानून की उचित प्रक्रिया का अधिकार है। जन दबाव और राजनीति का कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यह केवल विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए। इसी प्रकार,निर्दोष धार्मिक नेताओं और धार्मिक संस्थानों पर केवल उनकी मान्यताओं और लोकप्रियता के कारण हमला या उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। दोषियों को सजा और निर्दोषों को संरक्षण देने के बीच संतुलन होना चाहिए।

यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में हजारों धार्मिक संगठन और आध्यात्मिक संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा,आपदा प्रबंधन,पर्यावरण संरक्षण और वंचितों की सहायता जैसे क्षेत्रों में भी सराहनीय कार्य कर रही हैं। उन्होंने स्कूल,अस्पताल,सामुदायिक रसोईघर और धर्मार्थ कार्यक्रम स्थापित किए हैं जिनसे लाखों लोगों को लाभ मिलता है। ये बहुमूल्य योगदान हैं और सम्मान के पात्र हैं। यह धर्म या आध्यात्मिकता के विरुद्ध लड़ाई नहीं है-यह धर्म या आध्यात्मिकता के नाम पर होने वाले अपराध और शोषण के विरुद्ध लड़ाई है।

बच्चों में वैज्ञानिक सोच,संविधान के मूल्यों और नैतिक मूल्यों को विकसित करने की स्कूलों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंडोनेशिया और भारत ने अपने-अपने देशों के संविधान में वैज्ञानिक सोच को नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों में से एक के रूप में शामिल किया है। आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने से किसी भी धर्म पर संदेह नहीं होता;बल्कि इससे उन स्वार्थी और विकृत मानसिकता वाले लोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं।

नागरिक समाज संगठन, जिम्मेदार आध्यात्मिक शिक्षक,धार्मिक विद्वान,सामुदायिक नेता और अन्य लोग भी आध्यात्मिक संगठनों के मामले में अधिक पारदर्शिता,जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अधिक खुलापन,बेहतर नियमन और अधिक आय से विश्वास बढ़ेगा और वास्तविक आध्यात्मिक संगठनों की प्रामाणिकता बनी रहेगी।

सावधानी

प्रिया देवांगन प्रियू
राजिम गरियाबंद छत्तीसगढ़

बारिश का मौसम था। आसमान में काली घटाएं घिरने लगी थीं। वहीं छोटी छोटी लड़कियाँ खेलकूद कर मौसम का आनंद ले रही थीं। तभी जोर से बिजली चमकी और बच्चियाँ डर गईं। वहीं सहम कर एक दूसरे को देखने लगी। उनमें से एक बच्ची मिन्नी बोली अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। आंधी और बारिश शुरू होने वाली है। मिन्नी की बातों को उसकी सहेलियां अनसुना कर दीं। तभी विधि बोली तुम्हें जाना है तो जा सकती हो मिन्नी;हमें बारिश का मजा लेना है। मिन्नी बोली मेरे पिता जी कहते हैं कि जब जोर से बिजली चमके तो पेड़ों पर या खुले आसमान के नीचे नहीं ठहरना चाहिए, और जहाँ बिजली खंभा हो उसके आसपास तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इतना सुनकर मिन्नी का सभी मजाक उड़ाने लगे और बोले हमें कुछ नहीं होगा। मिन्नी तुम स्वयं डर रही हो और हमें भी डरा रही। मिन्नी चुपचाप अपने घर की तरफ चली गई।

मिन्नी के जाते ही थोड़ी ही देर में बारिश तेज होने लगी; बिजली का जोर जोर से चमकना,बादल का गरजना शुरू होने लगा। सभी लड़कियां शांत हो गईं। विधि बोली चलो उस पेड़ के नीचे जाकर खड़े होते हैं, जैसे ही बारिश कम होगी हम घर चले जाएंगे। जैसे ही कदम आगे बढ़ाए तो देखे कि पलक झपकते ही जोर से बादल गरजा और आसमान से वज्रपात हुआ। देखते ही देखते हरे भरे वृक्षों में आग लग गई; लड़कियां बाल बाल बचीं। एक-दूसरे को देखते हुए काँपने लगीं, मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी।

धीरे से प्रिंसी बोली विधि तुम्हारा घर थोड़ा पास है, हम तुम्हारे घर चलते हैं; यहाँ रुकना सही नहीं है। सभी ने हामी भरी और भींगते विधि के घर चली गईं।

विधि के मम्मी पापा विधि के साथ साथ उनकी सहेलियों को घर की तरफ आते देख लिए थे। सभी अंदर गए। पापा ने सब को एक एक तौलिया देते हुए पूछा इतनी बारिश में कहाँ से आ रहे तुम सब? सब के सब डर से शांत थे कि अब तो डांट पक्की है।

बताओ बेटा क्या हुआ? प्रिंसी ने पूरी घटना क्रम की जानकारी मम्मी-पापा को दी। विधि के पिता जी ने सबको डाँट लगायी और उन्हें समझाया-जीवन में हमेशा याद रखना कि हमें पेड़ या बिजली खम्भे के नीचे ऐसे समय नहीं खेलना या रहना चाहिए। तुम सबने देखा है कि आसमान से वज्रपात पेड़ों पर हुआ। जैसे हम दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं तो उससे आग उत्पन्न होती है, उसी तरह आसमान में भी बादल जब एक-दूसरे से टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है और वह धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण पेड़ों, बिजली खम्भों पर गिर जाती है। जिस जगह पर गिरती है उस जगह के आसपास पूरा आग लगा देती है, नष्ट कर देती है। इससे निकलने वाला धुआँ बहुत ही हानिकारक होता है। आसपास के जगहों के अलावा वहाँ पर जाने वाले मनुष्य के शरीर को भी नुकसान पहुँचाती है।`

बादल व बिजली के सम्बंध में जो बातें मिन्नी के पिता जी ने उसे समझाया, वही बातें वो तुम्हें बताई और तुम सब को मजाक लगा। सभी सिर झुकाये चुपचाप विधि के कमरे की तरफ चली गयीं। उन्हें आज एक अच्छा सबक मिल गया था।

मातृभूमि हमारी,स्नेह,संस्कृति और भाईचारे का अनूठा संगम

डॉ. मुश्ताक अहमद
हरदा,मध्यप्रदेश

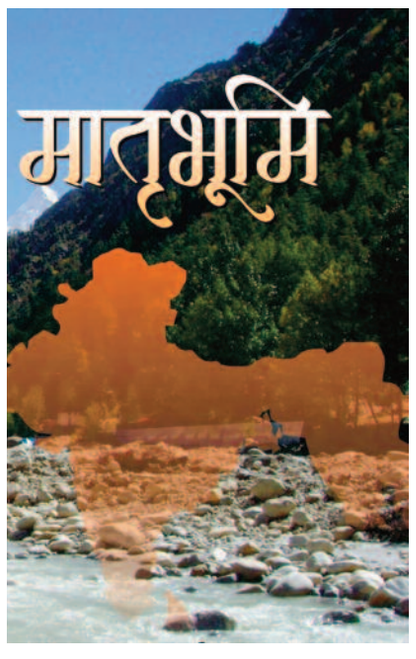

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अर्थात् जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। हमारी मातृभूमि केवल मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं है,बल्कि यह वह पवित्र आंचल है, जहाँ हर साँस में अपनापन, हर धड़कन में वंदना और हर संस्कृति में वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना बसती है। हमारी मातृभूमि की माटी में ममता है,इसकी हवाओं में संस्कारों की सुगंध है और इसके इतिहास में त्याग,बलिदान और अमर गाथाओं का गौरवशाली अध्याय है।

स्नेह और अपनापन,ममतामयी गोद...

मातृभूमि की परिभाषा केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है,यह एक भावनात्मक जुड़ाव है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को बिना किसी भेदभाव के अपना आंचल प्रदान करती है, उसी प्रकार हमारी मातृभूमि हर नागरिक को अपनी छाती से लगाकर रखती है। यहाँ की नदियाँ केवल जल नहीं बहातीं, बल्कि जीवन का अमृत सींचती हैं,यहाँ के खेत केवल अन्न नहीं उपजाते, बल्कि श्रम और स्नेह की कहानी कहते हैं। इसके कण-कण में रची-बची ममता हर व्यक्ति को कठिन से कठिन समय में भी संबल देती है।

संस्कृति और परंपराएं,विविधता में एकता,

हमारी मातृभूमि की सबसे बड़ी पहचान उसकी बहुरंगी और जीवंत संस्कृति है। यहाँ पग-पग पर पानी बदले और चार कोस पर वाणी बदले, फिर भी पूरा देश एक सूत्र में बंधा रहता है।

पर्व और उत्सव,,दीपावली का दीपपर्व,होली के सतरंगी रंग,ईद की सेवइयां,क्रिसमस के उल्लास और गुरुपर्व,यहाँ हर उत्सव को सब मिलकर मनाते हैं। कला और संगीत,शास्त्रीय संगीत से लेकर लोकगीतों तक, और शास्त्रीय नृत्यों से लेकर लोक कलाओं तक, हमारी परंपराएं हमारे पूर्वजों के उच्च आदर्शों, प्रकृति प्रेम और जीवन दर्शन को दर्शाती हैं। संस्कार हमारे यहाँ अतिथि को भगवान (अतिथि देवो भव) माना जाता है, बुजुर्गों का सम्मान और बड़ों का आशीर्वाद हमारी जीवनशैली का मुख्य आधार है।

आपसी भाईचारा,
अनेकता में एकता की मिसाल

हमारी मातृभूमि की असली ताक़त यहाँ का आपसी भाईचारा और सामाजिक समरसता है। यहाँ विभिन्न जातियों,धर्मों,भाषाओं और संप्रदायों के लोग आपस में इस तरह घुल-मिलकर रहते हैं जैसे दूध में शक्कर।

सुख हो या दुख, हर आपदा और हर उत्सव में पूरा समाज एक परिवार की तरह खड़ा नजर आता है।

यह वही भूमि है जहाँ प्रेम,करुणा,क्षमा और सहिष्णुता को सर्वोच्च मानवीय मूल्य माना गया है। यहाँ की हवाओं में एक-दूसरे के प्रति सम्मान और आदर की भावना घुली हुई है, जो किसी भी बाहरी आंधी या वैमनस्य के सामने अटूट दीवार बनकर खड़ी रहती है।

हमारी मातृभूमि हमारे अतीत का गौरव, वर्तमान का संबल और भविष्य का सपना है। इसकी रक्षा करना, इसके सम्मान को बनाए रखना और इसकी संस्कृति को संजोकर रखना हम सबका परम कर्तव्य है। आइए, इस पावन माटी को नमन करें और संकल्प लें कि इसके भाईचारे, संस्कृति और स्नेह रूपी प्राण को सदैव अक्षुण्ण बनाए रखेंगे।

सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दुस्तान हमारा!

फकीरों की संसार

उदय किशोर साह
जयपुर बांका बिहार

ये है फकीरों की अद्भुत संसार
यहाँ नहीं लगती दौलत की बाजार
हर जन मस्ती में यहाँ है चूर
चिन्ता फिक्र है जहाँ से कोसों दूर
दिल से है हर जन जन धनवान
लुट खसोट की नहीं कहीं है दुकान
हर शख्स अपने में है यहाँ मगरूर
वैमनस्यता को ना जगह है हुजूर
हर मन में बसा है शांति की अरमान
सब ग्रामीणों पे रब है यहाँ मेहरवान
हर चेहरे पे झलकता यहाँ पे नूर
खुदा को भी है ये नगर मंजूर
भाईचारा की सबका जहाँ कारीबार
बेईमानों की ना है कोई भी व्यापार
ईमानदारी की है जहाँ रस्म। दस्तूर
हर जन जन पे छाई है हँसी की सरूर
काश ! इस जगत सा होता ये संसार
दुश्मन भी शर्म से हो जाता शर्मसार
दोस्ती के लिये हर मानव होता मजबूर
मस्ती में झूमता कण कण में मजकूर

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

महापौर के निर्देश भी हवा में,पुलिस की पेट्रोलिंग भी गायब!

स्थानीय निवासी राकेश पांडेय का आरोप-'शिकायत की तो दबंग किराएदार बोला... बाबूपारा के लड़कों से पिटवा दूंगा...पुलिस और प्रशासन आज तक मूकदर्शक

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। वार्ड क्रमांक-4 स्थित एनडब्ल्यूजीएल चर्च के सामने शांतिपारा मैदान,जो शहर की प्रथम नागरिक महापौर मंजूषा भगत के निवास से कुछ ही दूरी पर स्थित है,वहां शाम ढलते ही कथित रूप से शराबखोरी,हुड़दंग, संदिग्ध गतिविधियों और दबंगई का अड्डा बन जाता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों, पुलिस को दिए गए आवेदन और महापौर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश देने के बावजूद आज तक हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। स्थानीय कलाकार एवं वार्डवासी राकेश पांडेय का आरोप है कि अब स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि असामाजिक तत्वों का विरोध करने वाले लोगों को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं।

सूरज ढलते ही अंधेरा ही नहीं,डर भी उतर आता है...: राकेश पांडेय बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद क्षेत्र की अधिकांश स्ट्रीट लाइटें बंद हो जाती हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर बाहरी लोग मैदान में जुटने लगते हैं। उनका कहना है कि वे सामाजिक विषयों पर वीडियो बनाते हैं,लेकिन अंधेरा और असामाजिक तत्वों की मौजूदगी के कारण उनका काम भी प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है, 'सूरज ढलते ही रोशनी चली जाती है और मेरे वीडियो बनाने का सपना अंधेरे में खो जाता है। लेकिन असली डर अंधेरे से नहीं, उन लोगों से है जो कैमरा देखते ही विरोध करने लगते हैं। बात केवल मना करने तक नहीं रहती, सीधे मारपीट और धमकी तक पहुंच जाती है।

घर के पीछे तीन घंटे तक खड़े रहे वाहन,पुलिस का कहीं पता नहीं : राकेश पांडेय बताते हैं कि हाल ही में उनके घर के पीछे महज 10 फीट की दूरी पर एक कार और दो मोटरसाइकिल करीब तीन घंटे तक खड़ी रहीं। इसके बावजूद न पुलिस की पेट्रोलिंग हुई और न किसी ने पूछताछ की। उनका कहना है कि यदि उसी दौरान कोई गंभीर अपराध हो जाता,तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता?

शराबखोरी रोकने पर मिली मारपीट और जान से मारने की धमकी : राकेश पांडेय ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अपने घर के पीछे खुलेआम शराब पी रहे युवकों का विरोध किया तो एक किराएदार युवक ने नशे की हालत में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और खुलेआम धमकी दी कि 'बाबूपारा के लड़कों से पिटवा दूंगा। 'उन्होंने बताया कि मामला केवल गाली-गलौज तक सीमित नहीं रहा,बल्कि उन्हें मारपीट कराने और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई।

शिकायत लेकर पहुंचे तो मां ने भी बेटे का साथ दिया : राकेश पांडेय के अनुसार जब वे शिकायत लेकर आरोपी युवक के किराए के मकान पहुंचे तो वहां मौजूद उसकी मां संगीता ने भी उल्टा उनसे अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि उसने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा...'जाओ, जो करना है कर लो। 'राकेश पांडेय का कहना है कि यह पूरा घटनाक्रम मकान मालकिन मंजू रानी श्रीवास्तव की मौजूदगी में हुआ।

मकान मालकिन ने समझाया, लेकिन किराएदार नहीं माने : पीड़ित के अनुसार मकान मालकिन ने स्थिति संभालने का प्रयास किया और आरोपियों को समझाया भी,लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। पीड़ित ने तत्काल ऐसे किराएदारों से मकान खाली कराने की मांग भी की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

महापौर ने दिए निर्देश,फिर भी कार्रवाई शून्य

राकेश पांडेय का कहना है कि उनकी शिकायत के बाद महापौर मंजूषा भगत ने स्वयं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को फोन कर असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के निर्देश दिए थे। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी मैदान में न तो नियमित पुलिस गश्त शुरू हुई और न ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई प्रभावी अभियान चलाया गया। स्थानीय लोगों का सवाल है कि यदि शहर की प्रथम नागरिक के निर्देशों का भी पालन नहीं हो रहा, तो आम नागरिक की शिकायतों का क्या महत्व रह जाता है?

शाम 7 बजे के बाद मैदान में लगता है बाहरी लोगों का जमावड़ा

स्थानीय लोगों के अनुसार दिन में मैदान लगभग खाली रहता है, लेकिन शाम सात बजे के बाद रात 11:30 से 12 बजे तक दोपहिया और चारपहिया वाहनों की कतार लग जाती है। अधिकांश लोग आसपास के मोहल्लों के नहीं,बल्कि गांधीनगर,गोधनपुर,बाबूपारा और शहर के अन्य इलाकों से आते हैं। आरोप है कि यहां शराब पीना,तेज आवाज में संगीत बजाना, जन्मदिन पार्टियां मनाना, स्काई शॉट जैसे पटाखे चलाना और बुलेट मोटरसाइकिल से जानबूझकर मिसफायर कर पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाना आम बात हो गई है।

कचरे से पटा मैदान,गंदगी के बीच उग आई झाड़ियां : मैदान में शराब की बोतलें,प्लास्टिक,डिस्पोजल,गुटखा पाउच, सिगरेट के पैकेट,कंडोम,चिकन दुकानों का कचरा और अन्य अपशिष्ट खुलेआम पड़े रहते हैं। लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण अब वहां झाड़ियां और घास भी उग आई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम की सफाई व्यवस्था भी यहां पूरी तरह नदारद है।

वार्डवासियों का सवाल-क्या किसी बड़ी वारदात के बाद जागेगा प्रशासन?

स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी वे असामाजिक तत्वों का विरोध करते हैं तो उन्हें धमकियां मिलती हैं। ऐसे माहौल में महिलाएं और बच्चे भय के साये में जी रहे हैं। लोगों ने सवाल उठाया है कि यदि शिकायतें,आवेदन,पुलिस को फोन,थाने में गुहार और महापौर के निर्देशों के बाद भी कार्रवाई नहीं होती,तो क्या प्रशासन किसी बड़ी वारदात का इंतजार कर रहा है?

शिकायत पर महापौर के निर्देश भी बेअसर, कार्रवाई अब भी गायब!

महापौर के घर से चंद कदम दूर अय्याशी अड्डा! कार्यवाही नहीं हो रही है

शराब, कंडोम, स्काई शॉट, बुलेट मिसफायर और गंदगी से दहशत में वार्डवासी

क्या-क्या हो रहा है मैदान में?

- शाम 7 बजे के बाद 11.30-12.00 तक शराबखोरी, अय्याशी और संदिग्ध गतिविधियां।
- शराब की बोतलें, कंडोम, गुटखा पाउच, सिगरेट पैकेट, डिस्पोजल और प्लास्टिक कचरे का अंबार।
- बुलेट से जानबूझकर मिसफायर, स्काई शॉट (20-25 राउंड) चलाकर दहशत फैलाते हैं।
- गाड़ियों में तेज म्यूजिक, हुड़दंग, जन्मदिन पार्टियों और रातभर जमावड़ा।
- मुर्गा दुकान का कचरा, पंख, बीट पचोनी, डिस्पोजल पत्तल मैदान में फेंके जाते हैं।
- मोहल्ले से कम, गांधीनगर, गोधनपुर और शहर के अन्य इलाकों से ज्यादा लोग आते हैं।
- कई किराएदारों का वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ।
- पुलिस पेट्रोलिंग नाव के बराबर, कभी-कभी दिन में या कई दिनों बाद रात में।

महापौर मंजूषा भगत ने पुलिस अधिकारियों को फोन पर दिए थे निर्देश

असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर जेल भेजे... फिर भी मैदान में आज भी जस का तस हालात!

प्रशासन से मांग...

वार्डवासियों ने आईजी,एसपी और कलेक्टर से मांग की है कि...

- मैदान में नियमित रात्रिकालीन पुलिस पेट्रोलिंग तत्काल शुरू की जाए।
- असामाजिक तत्वों और शराबखोरी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए।
- सभी किराएदारों का तत्काल पुलिस सत्यापन कराया जाए।
- धमकी देने वाले आरोपियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।
- हाईमास्ट लाइट,सीसीटीवी कैमरे और मैदान की घेराबंदी की जाए।
- नगर निगम नियमित सफाई कराए और अवैध कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाए।
- शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म,6.50 लाख रुपये की ठगी,आरोपी गिरफ्तार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने और उससे 6.50 लाख रुपये लेने के आरोप में मणिपुर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने रायपुर के पुरानी बस्ती थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 24 अप्रैल से 3 जुलाई 2026 के बीच बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छाछी निवासी परमेश्वर साहू ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने पीड़िता से 6 लाख 50 हजार रुपये भी ले लिए। प्रकरण में पुरानी बस्ती थाने में शून्य पर अपराध दर्ज किए जाने के बाद विवेचना के लिए केस डायरी मणिपुर थाना, अम्बिकापुर भेजी गई। यहां अपराध क्रमांक 137/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 एवं 351(3) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। लगातार प्रयास के बाद पुलिस टीम ने आरोपी परमेश्वर साहू (29 वर्ष), पिता हरलाल प्रसाद साहू, निवासी ग्राम छाछी, थाना कसडोल, जिला बलौदाबाजार को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने घटना स्वीकार कर ली। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी मणिपुर उप निरीक्षक सी.पी. तिवारी,महिला प्रधान आरक्षक मालती तिवारी तथा थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

गौहत्या कर मांस बेचने की तैयारी,चार नामजद व अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सीतापुर थाना क्षेत्र में गौहत्या कर मांस बेचने की तैयारी करने का आरोप लगाते हुए एक ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने चार नामजद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने (बीएनएस) एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ग्राम मुलाजिमपारा,सीतापुर निवासी अनिल दास ने शिकायत दर्ज कराई है कि 2 अगस्त की शाम करीब 6 बजे उसे सूचना मिली कि ग्राम तेन्दुखार के लिचिरमा स्थित कुंदन के खेत के पास कुछ लोग गौहत्या कर उसका मांस बिक्री के लिए रखे हुए हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक वह भवानी सिंह,शैलेश सिंह और वशिष्ठ दास के साथ मौके पर पहुंचा। वहां पहुंचने पर मौजूद लोग गौमांस छोड़कर भाग निकले। शिकायतकर्ता ने भागते हुए रामकुमार केरकेट्टा,बाबूलाल,चंदेश्वर और मुगुल को पहचानने का दावा किया है, जबकि अन्य लोगों की पहचान नहीं हो सकी। शिकायत के आधार पर सीतापुर पुलिस ने रामकुमार केरकेट्टा, बाबूलाल,चंदेश्वर, मुगुल तथा अन्य आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 325 तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 5 और 10 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

घर के सामने से बकरी चोरी,अपराध दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम उड़ूमकेला के बैगापारा में घर के सामने बंधी बकरी चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ चोरी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम उड़ूमकेला,बैगापारा निवासी विनोद पुलिस कोबताया कि 1 अगस्त की सुबह वह घर से कुछ दूरी पर खेत में हल चला रहा था। घर के सामने सड़क किनारे उसकी बकरी बंधी हुई थी। करीब 11.30 बजे उसकी मां मंगली बाई ने आवाज लगाई कि कुछ लोग बकरी चोरी कर ले जा रहे हैं। विनोद ने शोर सुनकर वह पहुंचा तो देखा कि तीन युवक उसकी बकरी को बाइक में लेकर भाग रहे हैं।

सरगुजा के छात्रों के भविष्य पर 'सीटों की कैंची'! अब सिंहदेव के बाद एनएसयूआई भी मैदान में...लॉ की 240 सीटें बहाल करने की उठी जोरदार मांग

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र,एनएसयूआई ने विधिक परिषद को सौंपा ज्ञापन,कहा...120 सीटों से सैकड़ों विद्यार्थी हो रहे वंचित,निजी कॉलेजों का बढ़ेगा दबाव

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर के एलएलबी पाठ्यक्रम की सीटें 240 से घटाकर 120 किए जाने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सीटें पूर्ववत 240 करने की मांग उठाई थी,वहीं अब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) भी छात्रों के समर्थन में खुलकर मैदान में उतर आया है। संगठन ने छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर सीटें बढ़ाने की मांग की है। राजनीतिक और छात्र संगठनों के एक साथ मुखर होने से यह मुद्दा अब केवल कॉलेज प्रशासन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सरगुजा संभाग के विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा बड़ा शिक्षा का मुद्दा बनता जा रहा है।

सिंहदेव बोले...गरीब और आदिवासी छात्रों का छिन जाएगा अवसर : पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि राजीव गांधी पीजी कॉलेज सरगुजा संभाग का प्रमुख और ऐतिहासिक शासकीय महाविद्यालय है, जहां दूरस्थ ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के हजारों छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि लॉ की सीटें 240 से घटाकर 120 करना आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। उन्होंने चेताया कि सीटों में कटौती से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को मजबूरन महंगे निजी लॉ कॉलेजों का रुख करना पड़ेगा, जो अधिकांश परिवारों की आर्थिक क्षमता से बाहर है। सिंहदेव ने यह भी कहा कि आदिवासी बहुल सरगुजा में कानूनी जागरूकता और स्थानीय स्तर पर विधि स्नातकों की आवश्यकता को देखते हुए सीटें कम करना क्षेत्रहित के विपरीत निर्णय है।

एनएसयूआई ने कहा...हर साल योग्य छात्र रह जाते हैं प्रवेश से वंचित : इधर, प्रदेश आरटीआई अध्यक्ष हिमांशु जायसवाल के मार्गदर्शन में एनएसयूआई के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता एवं उपाध्यक्ष गौतम गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद, बिलासपुर के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि राजीव गांधी पीजी कॉलेज सरगुजा संभाग का प्रमुख लॉ कॉलेज है,जहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एलएलबी में प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं,लेकिन केवल 120 सीटें होने के कारण अनेक योग्य और इच्छुक विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। पहले 240 सीटें होने से अधिक विद्यार्थियों को विधि शिक्षा का अवसर मिलता था। एनएसयूआई ने यह भी कहा कि सरगुजा संभाग के पांच जिलों के अधिकांश विद्यार्थी आर्थिक कारणों से दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसे में सरकारी कॉलेज की सीटें कम होना हजारों छात्रों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है।

एक मुद्दे पर कांग्रेस और छात्र संगठन की एक जैसी मांग

दिलचस्प बात यह है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव और एनएसयूआई,दोनों ने अलग-अलग माध्यमों से लगभग एक जैसी मांग उठाई है। दोनों का कहना है कि सीटों में कटौती से गरीब, ग्रामीण और आदिवासी विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के अवसर प्रभावित होंगे तथा निजी संस्थानों पर निर्भरता बढ़ेगी।

अब सरकार के फैसले पर टिकी निगाहें

लगातार बढ़ रहे विरोध और मांगों के बीच अब सभी की निगाहें राज्य सरकार पर टिकी हैं। यदि सरकार जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो यह मुद्दा छात्र आंदोलन का रूप ले सकता है। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का भी मानना है कि सरगुजा जैसे बड़े संभाग में विधि शिक्षा की बढ़ती मांग को देखते हुए सीटों की संख्या कम करने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

सीईओ को हटाने सरपंच संघ ने खोला मोर्चा,7 दिन का अल्टीमेटम

गलत गिरफ्तारी प्रकरण से बढ़ा विवाद, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच और तत्काल कार्यमुक्त करने की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जनपद पंचायत अंबिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) राजेश सिंह सेंगर के खिलाफ जिला सरपंच संघ ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को जिलेभर के सरपंच अंबिकापुर पहुंचे और कलेक्टर अजीत वसंत को ज्ञापन सौंपकर सीईओ को तत्काल पद से हटाने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। सरपंच संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सात दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर जिले के सभी सरपंच धरना-प्रदर्शन और लोकतांत्रिक आंदोलन करेंगे। सरपंच संघ का आरोप है कि ग्राम पंचायत चिताबहार में वर्ष 2020-21 के सामुदायिक शौचालय निर्माण में 1.75 लाख रुपए के कथित गबन मामले में वास्तविक जिम्मेदारों के बजाय सरईटिकरा के सरपंच एवं जिला सरपंच संघ

अध्यक्ष रामसाय मिंज के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कराया गया। बाद में न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत होने पर स्पष्ट हुआ कि रामसाय मिंज कभी चिताबहार पंचायत के सरपंच रहे ही नहीं। इसके बाद जनपद पंचायत ने रिकॉर्ड में त्रुटि स्वीकार करते हुए संशोधित पत्र भेजा।

ज्ञापन में लगाए गंभीर आरोप : सरपंच संघ ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि जनपद सीईओ के कार्यकाल में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। शिकायतों के आधार पर आदिवासी जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है, जबकि वास्तविक मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं कराई जाती। इससे पंचायत प्रतिनिधियों में भय और असंतोष का माहौल है।

संघ ने यह भी कहा कि वर्ष 2025 में भी सीईओ के स्थानांतरण की मांग को लेकर जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद राज्य शासन ने 30 जून 2026 को उनका स्थानांतरण रामानुजनगर जनपद पंचायत कर दिया, लेकिन अब तक उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है। इससे शासन के आदेशों के पालन पर भी सवाल उठ रहे हैं।

चार प्रमुख मांगें : सरपंच संघ ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि जनपद पंचायत अंबिकापुर के सीईओ को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानांतरण आदेश का पालन कराया जाए। साथ ही उनके कार्यकाल में पंचायत प्रतिनिधियों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। रामसाय मिंज की गिरफ्तारी प्रकरण की जिम्मेदारी तय कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए तथा भविष्य में पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से पहले निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए।

आंदोलन की चेतावनी : सरपंच संघ ने कहा है कि यदि सात दिनों के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जिलेभर के सरपंच जनपद पंचायत अंबिकापुर के सामने धरना-प्रदर्शन करेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

चरित्र पर शक कर पत्नी से मारपीट का आरोप,पति,जेठ समेत छह पर एफआईआर दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

महिला ने अपने पति समेत ससुराल पक्ष के छह लोगों पर मारपीट, गाली-गलौज,जान से मारने की धमकी और घर में बंधक बनाने का आरोप लगाया है। महिला ने थाना गांधीनगर में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम रनपुरकला निवासी सुनीता यादव ने शिकायत में बताया है कि 10 जुलाई 2026 की दोपहर करीब 2 बजे वह घर के आंगन में गाय को पानी पिलाने के बाद खड़ी थी। इसी दौरान उसके पति विजय शंकर यादव और जेठ टीकम प्रसाद यादव पहुंचे। पति ने चरित्र पर संदेह जताते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी और डंडे से मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान जान से मारने की धमकी भी दी गई, जबकि जेठ टीकम प्रसाद ने पति को उकसाते हुए उसे खत्म कर देने की बात कही। महिला का आरोप है कि शाम को पति सामान्य व्यवहार करता रहा, लेकिन रात करीब 9.10 बजे जेठ के दोबारा पहुंचने पर सास सुकवरिया यादव, जेठ इंद्रजीत यादव और चाचा ससुर प्रभु यादव भी उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगे। इसके बाद अन्य परिजनों को भी बुलाया गया। शिकायत में महिला ने कहा है कि वह डर के कारण गांव के अयोध्या प्रसाद यादव के घर चली गई थी, लेकिन रात में वहां से भी उसे जबरन घर ले जाकर फिर मारपीट की गई। आरोप है कि उसके बाद घर के बाहर ताला लगा दिया गया और दीवार पर सीढ़ी लगाकर ऐसा माहौल बनाया गया,जिससे उस पर चोरी का आरोप लगाया जा सके। महिला ने बताया कि अगले दिन 11 जुलाई को उसके पिता पारसनाथ यादव पुलिस के साथ पहुंचे, तब उसे घर से बाहर निकाला गया। मारपीट में उसके दोनों पैर, जांघ, पीठ, सिर और हाथ में चोटें आई हैं। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके पति ने गांव के कुछ लोगों की मौजूदगी में घर का सामान, राशन कार्ड, आधार कार्ड, अन्य दस्तावेज और नकदी भी अपने कब्जे में ले ली। उसने आवेदन में घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं।

शिक्षिकाओं ने प्रधानपाठक पर लगाए गंभीर आरोप, चौकी में शिकायत

स्तनपान के दौरान छिपकर देखने और मासिक धर्म पर प्रमाणपत्र मांगने का आरोप,विधायक ने निष्पक्ष जांच के दिए निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत शासकीय मिडिल स्कूल भरूहीबांस के प्रधानपाठक के खिलाफ दो शिक्षिकाओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए बलंगी चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। दोनों शिक्षिकाओं ने अलग-अलग घटनाओं का उल्लेख करते हुए कार्यस्थल पर मानसिक प्रताड़ना और असुरक्षा का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत क्षेत्रीय विधायक से भी की गई है। एक शिक्षिका ने शिकायत में कहा है कि वह अपने दुधमुंहे बच्चे के साथ स्कूल आती है। बच्चे को स्तनपान कराने के दौरान प्रधानपाठक मनोज गुप्ता ने कथित रूप से छिपकर देखने का प्रयास किया। शिक्षिका का कहना है कि इस घटना से उसकी गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंची है तथा वह कार्यस्थल पर स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसी स्कूल की दूसरी शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि प्रधानपाठक मासिक धर्म के दौरान अवकाश लेने पर प्रमाणपत्र लाने की बात कहते हैं।

CMYK

छत्तीसगढ़ का शायद पहला 'मवेशी शौचालय'! इंसानों ने किया बहिष्कार,गाय-भैंस ने संभाली जिम्मेदारी

लाखों की लागत से बना सार्वजनिक शौचालय बना पशुओं का विश्राम गृह,सफाई व्यवस्था भी भगवान भरोसे...

-संवाददाता-
पटना/कोरिया,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए सार्वजनिक शौचालयों का उद्देश्य था कि राहगीरों और आम नागरिकों को स्वच्छ एवं सुरक्षित सुविधा मिले,लेकिन कोरिया जिले की नवीन नगर पंचायत पटना में एक ऐसा सार्वजनिक शौचालय है, जिसने शायद अपनी उपयोगिता की नई परिभाषा ही लिख दी है, यहां इंसानों की जगह अब मवेशियों ने कब्जा जमा लिया है, अगर कोई नियमित रूप से इस शौचालय का उपयोग कर रहा है,तो वे हैं–गाय, बैल और अन्य आवारा मवेशी,राष्ट्रीय राजमार्ग पर, नगर पंचायत कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीच स्थित यह शौचालय स्थान के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है,दिनभर यहां से सैकड़ों लोग गुजरते हैं, मरीज अस्पताल आते हैं,यात्री रुकते हैं,लेकिन शौचालय का दरवाजा इंसानों के लिए शायद कम और मवेशियों के लिए ज्यादा खुला रहता है।

स्वच्छता अभियान या पशुधन सुविधा केंद्र?-

शौचालय के भीतर प्रवेश करते ही सबसे पहले स्वागत किसी सफाई कर्मचारी से नहीं, बल्कि गोबर से होता है, कई बार अंदर मवेशी आराम फरमाते मिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने इस भवन को अपना स्थायी आश्रय घोषित कर दिया है, व्यंग्य यह है कि शौचालय तो उपयोग में आ रहा है, बस उपयोगकर्ता बदल गए हैं।

जिम्मेदार कौन?-

सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सार्वजनिक शौचालय की देखरेख और साफ-सफाई की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? यदि नगर पंचायत के अधीन यह शौचालय संचालित है, तो क्या कभी किसी अधिकारी या कर्मचारी ने इसकी वास्तविक स्थिति देखने की जरूरत महसूस की? यदि सफाई के लिए बजट खर्च हो रहा है, तो वह सफाई आखिर कागजों में हो रही है या धरातल पर?

राहगीरों की बढ़ी परेशानी–स्थानीय लोगों का कहना है कि सार्वजनिक सुविधा के नाम पर बनाया गया यह शौचालय अब लोगों के किसी काम का नहीं रह गया है,महिलाएं, बुजुर्ग और बाहर से आने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने के बजाय निराशा हाथ लगती है, वहीं मवेशियों के जमावड़े और गंदगी के कारण आसपास दुर्गंध भी फैलती रहती है।

व्यंग्य में बड़ा सवाल- यदि यही हाल रहा तो शायद आने वाले समय में इस शौचालय के बाहर एक नया बोर्ड लगाना पड़े-'सार्वजनिक शौचालय (केवल मवेशियों हेतु)' और इंसानों के लिए लिखा जाए-'कृपया असुविधा के लिए खेद है,सुविधा फिलहाल पशुधन के उपयोग में है। '

जवाब का इंतजार- अब देखना यह होगा कि नगर पंचायत इस 'मवेशी शौचालय' को फिर से आम नागरिकों के उपयोग लायक बनाती है या फिर यह लाखों रुपये की लागत से बनी सरकारी संपत्ति पशुओं के स्थायी विश्राम स्थल के रूप में ही अपनी पहचान बनाए रखेगी,आखिर सवाल सिर्फ एक शौचालय का नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन,जवाबदेही और स्वच्छता अभियान की वास्तविक तस्वीर का भी है।

अंडरएज ड्राइविंग पर सरगुजा पुलिस सख्त,स्कूलों में शुरू हुआ जागरूकता अभियान

विक्टोरिया पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों को दी यातायात नियमों की जानकारी,अभिभावकों से भी नाबालिगों को वाहन न देने की अपील

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

नाबालिगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अंडरएज ड्राइविंग पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस ने जिले के स्कूलों में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत यातायात पुलिस की टीम ने सोमवार को विक्टोरिया पब्लिक स्कूल पहुंचकर छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी और बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन नहीं चलाने की समझाइश दी। पुलिस के अनुसार, शासन के निर्देश तथा

डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में यह अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नाबालिग विद्यार्थियों की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें दुर्घटनाओं से बचाना है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को हेलमेट पहनने,यातायात नियमों का पालन करने तथा स्कूल आने-जाने के लिए अधिकृत स्कूल वाहन या परिजनों के साथ ही यात्रा करने की सलाह दी गई। पुलिस ने जिले के सभी विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को भी निर्देश दिए हैं कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी छात्र-छात्रा को दोपहिया वाहन से विद्यालय आने की अनुमति न दी जाए। यदि कोई विद्यार्थी अंडरएज ड्राइविंग करते हुए पाया जाता है तो पहले उसे और उसके परिजनों को बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा पुलिस ने बताया कि जिलेभर के विभिन्न स्कूलों में प्रतिदिन ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है ताकि वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने के लिए न दें। पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्हें अंडरएज ड्राइविंग से दूर रखें। अभियान आगामी दिनों में भी लगातार जारी रहेगा।

जनदर्शन में मंत्री राजेश अग्रवाल ने सुनीं लोगों की समस्याएं

लखनपुर स्थित निवास पर पहुंचे बड़ी संख्या में नागरिक, अधिकारियों को त्वरित निराकरण के दिया निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने सोमवार को लखनपुर स्थित अपने निवास पर आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों और नगरीय क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं और मांगें लेकर पहुंचे। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में नागरिकों ने पेयजल,सड़क,बिजली,स्वास्थ्य,शिक्षा, राजस्व,सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पर्यटन विकास तथा सांस्कृतिक गतिविधियों सहित विभिन्न जनहित के मुद्दे उठाए। मंत्री अग्रवाल ने प्रत्येक आवेदन का अवलोकन कर विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई करने और प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जनता का

विश्वास सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है और शासन की योजनाओं का उद्देश्य तभी सफल होगा, जब जरूरतमंद लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान हो। उन्होंने कहा कि जनदर्शन आम नागरिकों और शासन के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम है तथा सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक भटकना न पड़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से जनप्रतिनिधि और प्रशासन लगातार लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं।

नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार

करम्हा गांव की घटना, पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

करम्हा गांव में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के

अनुसार, 2 अगस्त को नाबालिग पीड़िता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई कि करम्हा निवासी गौतम राम उर्फ सटेल (40 वर्ष) ने उसे अकेला पाकर लज्जा भंग करने की नीयत से जबरन छेड़छाड़ की। पीड़िता मौके से भागकर घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 537/26 दर्ज कर बीएनएस की धारा 74, 75(2), 76 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 एवं 12 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

72 घंटे में आरोपी गिरफ्तार करो,वरना कोतवाली का घेराव

भपौली में नाबालिग से दुराचार मामले में महिला कांग्रेस का अल्टीमेटम,पुलिस पर लापरवाही का आरोप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

भपौली में नाबालिग से दुराचार के मामले में आरोपी की 72 घंटे के भीतर गिरफ्तारी नहीं होने पर महिला कांग्रेस ने कोतवाली थाना घेरने की चेतावनी दी है। इस संबंध में महिला कांग्रेस शहर इकाई की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष सीमा सोनी ने कहा कि जिले में नाबालिग,विशेषकर आदिवासी बच्चियों के साथ हो रहे अपराधों के मामलों में पुलिस का रवैया संवेदनशील नहीं है। उनका आरोप है कि पुलिस की ढिलाई के कारण कई मामलों में आरोपियों को कानून से बच निकलने का अवसर मिल रहा है।

'राशन के लिए भटक रहे लोग, दुकानें बंद' : कांग्रेस ने खाद्य विभाग का घेराव कर उठाया गंभीर सवाल

एपीएल को चावल नहीं, अंत्योदय हितग्राहियों को चार माह से शक्कर नहीं; ओटीपी बंद होने से बुजुर्ग भी परेशान, नियमित राशन वितरण की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

शहर के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मंडल क्षेत्र में राशन वितरण में कथित अनियमितताओं और राशन दुकानों के नियमित रूप से नहीं खुलने के विरोध में सोमवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला खाद्य अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि एपीएल कार्डधारकों को चावल नहीं मिल रहा है, अंत्योदय हितग्राहियों को पिछले चार माह से शक्कर का वितरण बंद है और बायोमैट्रिक आधारित व्यवस्था के कारण कई बुजुर्ग राशन से वंचित हो रहे हैं। मंडल अध्यक्ष निकी खान के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में शहर ब्लॉक कांग्रेस

अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह धंजल, जिला उपाध्यक्ष मो. इस्लाम, पार्षद मो. हसन एवं मो. बाबर सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने खाद्य अधिकारी को बताया कि बायोमैट्रिक ओटीपी व्यवस्था बंद होने और केवल फिंगरप्रिंट सत्यापन पर निर्भरता के कारण कई बुजुर्गों के अंगूठे का मिलान नहीं हो पा रहा है, जिससे वे अपना निर्धारित राशन नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसी स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए ताकि कोई भी पात्र हितग्राही खाद्यान्न से वंचित न रहे। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कई राशन दुकानें निर्धारित समय पर नहीं खुल रही हैं, जिससे आम लोगों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र की सभी राशन दुकानों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने और वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग की। जिला खाद्य अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने वालों में मंडल अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सिंह, सौरभ फिलिप, काजू खान, विजय सोनी, शमसु अंसारी, अब्दुल वाहिद, अजहर मंसूरी, मो. औरंगजेब सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सावन महीने के पहले सोमवार को हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

श्रावण मास के पहले सोमवार को शहर और जिले भर के शिवालयों में हर-हर महादेव और जय ओम शिवकारा के जयकारे गूंजते रहे। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शिव मंदिरों के साथ-साथ अन्य मंदिरों में भी दिनभर भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, फूल, दूध, दही, घी और जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। सावन का पहला सोमवार होने के कारण मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई थीं। समिति द्वारा भक्तों की सुविधा हेतु विशेष व्यवस्था की गई थी। 30 जुलाई से सावन मास की शुरुआत हो चुकी है। शहर के शंकर घाट स्थित शिव मंदिर,जोड़ा पीपल मंदिर,सांडबार बैरियर,गांधीनगर, नमनाकला,गंगापुर सहित अन्य मंदिरों में भी सुबह से भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर सुख-शांति की कामना की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सावन मास में सोमवार का विशेष महत्व है। इस दिन को भगवान शिव का दिन माना

जाता है और जो भक्त नियमित पूजा न कर सकें, उन्हें सावन के सोमवार को व्रत और पूजा जरूर करनी चाहिए। शहर के शंकर घाट में श्रद्धालुओं ने स्नान कर जल उठाया और मंदिर पहुंचकर शिवजी का दूध व जल से अभिषेक किया।

क्या एमसीबी से शुरू हो रही है सरगुजा की नई रेल क्रांति? लरंग साय के ऐतिहासिक संघर्ष के बाद श्याम बिहारी जायसवाल की नई पहल चर्चा में...

लरंग साय के बाद क्या रेल विकास की नई पहचान बन रहे हैं श्याम बिहारी जायसवाल?

सरगुजा की रेल कनेक्टिविटी में नई परियोजनाओं ने छेड़ी नई बहस

रेल विकास की विरासत और नया नेतृत्व, क्या श्याम बिहारी जायसवाल दोहरा पाएंगे लरंग साय का विकास मॉडल?

सरगुजा की रेल राजनीति में नया अध्याय लरंग साय के संघर्ष से श्याम बिहारी जायसवाल की विकास यात्रा तक

इतिहास दोहराया नहीं जाता, नई विरासत बनाई जाती है क्या रेल विकास के नए अध्याय के केंद्र में हैं श्याम बिहारी जायसवाल?

602 करोड़ की परियोजना के बाद श्याम बिहारी जायसवाल की भूमिका पर शुरू हुई चर्चा

क्या सरगुजा को मिल रहा है दूसरा 'रेल पुरुष'?

स्वर्गीय लरंग साय ने आंदोलन से बिछाई थी रेल विकास की नींव,क्या स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल विकास परियोजनाओं से लिख रहे हैं नया अध्याय?

न्यूज डेस्क

रायपुर/चिरमिरी,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा अंचल का इतिहास केवल राजनीतिक संघर्षों का इतिहास नहीं है,बल्कि विकास के लिए चले लंबे जनआंदोलनों का भी इतिहास है, सड़क,शिक्षा,स्वास्थ्य और रेल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए इस क्षेत्र को वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा,इन्हीं संघर्षों में यदि किसी एक नाम को सबसे अधिक सम्मान के साथ याद किया जाता है तो वह है स्वर्गीय लरंग साय,सरगुजा के लोगों के लिए लरंग साय केवल एक जनप्रतिनिधि नहीं थे,उन्हें उस नेता के रूप में याद किया जाता है जिसने यह समझ लिया था कि यदि क्षेत्र का विकास करना है तो उसे रेल नेटवर्क से जोड़ना ही होगा,उस दौर में जब सरगुजा देश के सबसे पिछड़े और दूरस्थ इलाकों में गिना जाता था,तब उन्होंने रेलवे को विकास का सबसे बड़ा माध्यम माना और इसे जन आंदोलन का रूप दिया,आज,कई दशक बाद एक बार फिर सरगुजा और विशेषकर मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) क्षेत्र में रेल विकास की चर्चा तेज है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पाराडोल से नागपुर रोड तक लगभग 602 करोड़ रुपये की नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए टेंडर जारी होने के बाद एक नई राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है–क्या वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री और चिरमिरी विधायक श्याम बिहारी जायसवाल सरगुजा में रेल विकास की नई पहचान बन रहे हैं? यह तुलना भावनात्मक नहीं, बल्कि तथ्यों और कार्यों के आधार पर समझने की जरूरत है। बता दे की मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित रेल विस्तार परियोजना अब धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) ने पाराडोल से नागपुर रोड स्टेशन तक नई ब्रॉडगेज सिंगल रेल लाइन के निर्माण तथा बोरीडांड-चिरमिरी रेलखंड के स्लूइंग कार्य के लिए ई-टेंडर जारी कर दिया है। लगभग 601.90 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर दो वर्ष (730 दिन) में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, यह परियोजना न केवल चिरमिरी की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी,बल्कि पूरे एमसीबी जिले के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास को भी नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।

करीब साढ़े 17 किलोमीटर लंबी होगी नई रेल लाइन

परियोजना के तहत पाराडोल टेकऑफ प्वाइंट (किमी 947.257) से नागपुर रोड स्टेशन (किमी 964.820) तक नई ब्रॉडगेज सिंगल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही बोरीडांड-चिरमिरी लाइन के किमी 946.640 से 947.257 के बीच स्लूइंग कार्य भी होगा,जिससे नई लाइन को मौजूदा नेटवर्क से जोड़ा जाएगा,नई लाइन की लंबाई लगभग 17.5 किलोमीटर होगी,जो भविष्य की यात्री और माल परिवहन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित की जाएगी।

जब रेल केवल सुविधा नहीं,सपना थी

आज जिस सरगुजा में रेल सुविधाओं का विस्तार दिखाई देता है,वहां एक समय ऐसा था जब रेल केवल लोगों का सपना थी,अंबिकापुर तक रेल पहुंचाने की मांग वर्षों तक उठती रही,उस समय लरंग साय ने इस मांग को केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं रहने दिया बल्कि जनता का आंदोलन बना दिया,उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक लगातार यह मुद्दा उठाया कि यदि सरगुजा को मुख्यधारा से जोड़ना है तो रेल संपर्क आवश्यक है, उनके संघर्ष का परिणाम यह रहा कि अंबिकापुर रेल मानचित्र पर आया और क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलीं।

लरंग साय की पहचान क्यों बनी? लरंग साय की पहचान इसलिए नहीं बनी कि उनके समय में केवल कोई रेल लाइन स्वीकृत हुई,उनकी पहचान इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने वर्षों तक लगातार आवाज उठाई,रेल को राजनीतिक नहीं बल्कि क्षेत्रीय विकास का विषय बनाया,सरगुजा के लोगों को एक साझा मांग के लिए एकजुट किया,अंबिकापुर-बरवाड़ीह जैसी बड़ी परियोजना के लिए लगातार प्रयास किए,यही कारण है कि आज भी सरगुजा में रेल विकास की चर्चा होती है तो उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है।

क्या यही तुलना का आधार है?–यहीं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है, क्या केवल एक बड़ी परियोजना किसी नेता की तुलना लरंग साय से कराने के लिए पर्याप्त है? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास किसी एक घोषणा से नहीं बनता, इतिहास लगातार किए गए प्रयासों से बनता है,यदि आने वाले वर्षों में चिरमिरी रेल नेटवर्क का विस्तार होता है,नई यात्री ट्रेनें शुरू होती हैं,माल परिवहन बढ़ता है,एमसीबी राष्ट्रीय रेल नेटवर्क में और मजबूत होता है,तथा सरगुजा के अन्य लंबित रेल प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ते हैं,तब निश्चित रूप से श्याम बिहारी जायसवाल का नाम रेल विकास के संदर्भ में प्रमुखता से लिया जाएगा।

दो दौर,दो परिस्थितियां,दोनों नेताओं की परिस्थितियां भी अलग थीं...

लरंग साय
- विपक्ष और जनसंघर्ष की राजनीति।
- रेल के लिए आंदोलन।
- लंबे समय तक लगातार मांग।
- केंद्र सरकार तक दबाव।

श्याम बिहारी जायसवाल
- सरकार का हिस्सा।
- मंत्री के रूप में निर्णय प्रक्रिया तक पहुंच।
- परियोजनाओं को प्रशासनिक गति दिलाने की भूमिका।
- स्वीकृत योजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी।

इसलिए दोनों की भूमिका अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही दिखाई देता है...

रेल के माध्यम से क्षेत्र का विकास।

सरगुजा में रेल विकास अभी अधूरा है–यह भी सच है कि सरगुजा का रेल विकास अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, आज भी कई महत्वपूर्ण मांगें लंबित हैं अंबिकापुर-बरवाड़ीह रेल लाइन,रेल सेवाओं का विस्तार,नई एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत,औद्योगिक रेल कॉरिडोर,पर्यटन आधारित रेल सुविधाएं,यदि इन परियोजनाओं पर भी गति आती है तो सरगुजा का विकास एक नए चरण में प्रवेश करेगा।

राजनीति नहीं,विकास की प्रतिस्पर्धा हो–यदि किसी नेता की तुलना किसी ऐतिहासिक जननेता से की जाती है तो उसका आधार राजनीतिक नारे नहीं,बल्कि ठोस उपलब्धियां होनी चाहिए,यदि श्याम बिहारी जायसवाल अपने कार्यकाल में रेल विस्तार, स्वास्थ्य,सड़क,शिक्षा,औद्योगिक निवेश जैसे क्षेत्रों में स्थायी परिवर्तन ला पाते हैं,तब इतिहास स्वयं उनका मूल्यांकन करेगा,ऐसी तुलना जनता करती है, समाचार पत्र नहीं।

इतिहास का फैसला समय करता है–किसी भी नेता को इतिहास में स्थान चुनावी जीत से नहीं मिलता,स्थान मिलता है उसके कार्यों से, उसके संघर्ष से,उसके द्वारा छोड़ी गई विकास की विरासत से,स्वर्गीय लरंग साय आज इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि उनका संघर्ष परिणाम में बदल गया,अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि क्या श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयास भी आने वाले वर्षों में एमसीबी और सरगुजा की रेल व्यवस्था में स्थायी परिवर्तन ला पाते हैं,यदि यह परियोजना समय पर पूरी होती है और इसके बाद भी रेल विस्तार की कड़ी आगे बढ़ती है,तो भविष्य में इतिहास स्वयं तय करेगा कि सरगुजा को रेल विकास के क्षेत्र में एक और ऐसा जनप्रतिनिधि मिला,जिसने क्षेत्र की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इतिहास किसी को उपाधि नहीं देता,इतिहास उसे याद रखता है जिसने विकास को स्थायी विरासत बनाया हो।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया विकास का नया अध्याय...

समय बदला,सरगुजा संभाग का पुनर्गठन हुआ,एमसीबी नया जिला बना,इसी बीच चिरमिरी के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल राज्य सरकार में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री बने,सरकार में आने के बाद उनके गृह क्षेत्र में रेल विकास की गति भी तेज दिखाई देने लगी,अब पाराडोल-नागपुर रोड नई रेल लाइन के लिए लगभग 602 करोड़ रुपये की परियोजना का टेंडर जारी होना इस दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है,यदि यह परियोजना समय पर पूरी होती है तो चिरमिरी की रेल व्यवस्था बदलेगी,कोयला परिवहन को नई गति मिलेगी,एमसीबी जिले की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी,भविष्य में नई ट्रेनों की संभावनाएं बढ़ेंगी,क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी,उन्होंने कहा कि नई रेल लाइन बनने से एमसीबी जिले की देश के अन्य हिस्सों से रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी,औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी,उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए आगे भी लगातार प्रयास जारी रहेंगे।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी पूरी परियोजना

रेल परियोजना केवल नई पटरी बिछाने तक सीमित नहीं रहेगी, इसके तहत–बड़े रेल पुलों का निर्माण, रोड ओवर ब्रिज (आरओबी), रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी),वायाडक्ट पुल, आधुनिक सिग्नल एवं दूरसंचार प्रणाली, ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क,पूर्ण विद्युतीकरण,पाराडोल जंक्शन का विकास, नागपुर रोड स्टेशन से संबंधित निर्माण, तथा नई चिरमिरी स्टेशन से जुड़े विकास कार्य भी किए जाएंगे, इन सुविधाओं के बाद यह पूरा रेल खंड आधुनिक तकनीक और बेहतर सुरक्षा मानकों से लैस हो जाएगा।

यात्रियों को भी मिलेगी बेहतर सुविधा

इस परियोजना का लाभ केवल माल परिवहन तक सीमित नहीं रहेगा, नई रेल लाइन बनने के बाद चिरमिरी और एमसीबी जिले के लोगों को भी अधिक सुगम रेल सुविधा मिलने की उम्मीद है,बेहतर कनेक्टिविटी से यात्रियों के आवागमन में सुविधा होगी, यात्रा समय में सुधार आएगा और भविष्य में नई रेल सेवाओं की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।

विश्व बाघ दिवस पर विद्यार्थियों ने दिया 'बाघ बचाओ,जंगल बचाओ' का संदेश

स्वामी आत्मानंद विद्यालय सोनहत में जागरूकता कार्यक्रम एवं चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित,पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प...

-संवाददाता-

सोनहत (कोरिया),03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

विश्व बाघ दिवस के अवसर पर स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, सोनहत में वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता को समर्पित प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों में प्रकृति, वन्यजीवों और जैव विविधता के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के उद्देश्य से जागरूकता सत्र एवं वृहद चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई,विद्यालय परिसर 'बाघ बचाओ,जंगल बचाओ'तथा 'प्रकृति संरक्षण ही मानव जीवन का आधार है'जैसे संदेशों से गूंज उठा।

बाघ संरक्षण के महत्व से विद्यार्थियों को कराया गया अवगत–कार्यक्रम की शुरुआत विश्व बाघ दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए की गई, शिक्षकों ने विद्यार्थियों को बताया कि बाघ केवल भारत का राष्ट्रीय पशु ही नहीं,बल्कि वन पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रहरी भी है, उन्होंने कहा कि यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो बाघ सुरक्षित रहेंगे और यदि बाघ सुरक्षित रहेंगे तो संपूर्ण जैव विविधता तथा प्राकृतिक संतुलन भी सुरक्षित रहेगा,विद्यार्थियों को बाघों की घटती संख्या के कारणों और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

चित्रों में उभरा प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का संदेश–कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में कक्षा पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, नन्हे बच्चों से लेकर वरिष्ठ विद्यार्थियों तक सभी ने अपनी कल्पनाशक्ति और कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए बाघ, घने जंगल,वन्यजीव, नदियां,हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य को रंगों के माध्यम से जीवंत किया। विद्यार्थियों ने अपने चित्रों के जरिए वन संरक्षण और जैव विविधता बचाने का प्रभावशाली संदेश दिया, प्रतियोगिता में कक्षा 10वीं की छात्राएं भूमिका,प्रियंशी एवं अनुराधा ने बाघ संरक्षण और पर्यावरण संतुलन पर आधारित आकर्षक एवं संदेशपरक चित्र प्रस्तुत किए, जिनकी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने सराहना की।

पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण–शिक्षकों ने विद्यार्थियों को बताया कि अनियंत्रित वनों की कटाई,अवैध शिकार और प्राकृतिक आवासों के लगातार सिकुड़ने से बाघों का अस्तित्व प्रभावित हो रहा है,उन्होंने कहा कि बाघ खाद्य श्रृंखला के शीर्ष शिकारी हैं और उनकी मौजूदगी पूरे वन तंत्र के स्वस्थ होने का संकेत है। इसलिए बाघों का संरक्षण केवल वन्यजीवों की रक्षा नहीं,बल्कि जंगलों,जल स्रोतों, पर्यावरण और मानव जीवन की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है,विद्यार्थियों को यह भी समझाया गया कि पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत छोटी-छोटी जिम्मेदारियों से होती है,अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना,प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना,वन्यजीवों के प्रति संवेदनशील रहना और पर्यावरण संरक्षण अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

विद्यालय परिवार ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता की सराहना की–विद्यालय के प्राचार्य एवं समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और उत्साह की सराहना की, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों में सामाजिक उत्तरदायित्व,प्रकृति प्रेम और संरक्षण की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं,साथ ही विद्यार्थियों को भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया।

प्रकृति संरक्षण का लिया सामूहिक संकल्प

कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि वे प्रकृति एवं वन्यजीवों की रक्षा के लिए सदैव जागरूक रहेंगे, अधिक से अधिक लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित करेंगे तथा'बाघ बचाओ,जंगल बचाओ' के संदेश को समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे साथ ही सकारात्मक संदेश दिया गया और कहा गया की जब सुरक्षित रहेगा बाघ, तभी सुरक्षित रहेंगे जंगल,और जब जंगल सुरक्षित रहेंगे,तभी मानव जीवन,जल,वायु और सम्पूर्ण पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला

कथित चूक की शिकायत पर भी नहीं हुई विभागीय जांच!

सरकारी आदेश में 'नमूना सहायक' का नाम दर्ज, शिकायतकर्ता से मांगे सबूत

सरकारी आदेश की सूची (05-11-2023)

प्रधानमंत्री के सुरजपुर दौरें (07-11-2023) के लिए भोजन परीक्षण दल

क्रम	नाम	पद	भूमिका
1.	डॉ. जगवंधन सिंह	चिकित्सा अधिकारी	भोजन परीक्षण
2.	नितीश कुमार मिंश्रा	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	भोजन परीक्षण
3.	सुमित त्रिपाठी	नमूना सहायक	भोजन परीक्षण

नितीश कुमार मिश्रा पर गंभीर आरोप

- फर्जी 'नमूना सहायक' को बनाकर भोजन परीक्षण दल में शामिल किया गया
- टेस्टिंग लैब, FOSTAC एजेंसियों से कमीशन
- FBO से अवैध वसूली और पद का दुरुपयोग
- नकली मिलावटी उत्पादों को संरक्षण देने के आरोप

क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी शिकायत भी जांच के लायक नहीं थी?

रिकॉर्ड सरकार के पास,फिर भी शिकायतकर्ता से मांगे गए साक्ष्य...

सरकारी रिकॉर्ड की जांच करने के बजाय शिकायतकर्ता से मांगे सबूत,उप सचिव की भूमिका पर उठे सवाल...

-संवाददाता-

सूरजपुर/रायपुर,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता मानी जाती है,प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा से जुड़े प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी तय होती है और भोजन परीक्षण जैसी प्रक्रिया को भी अत्यंत संवेदनशील माना जाता है,ऐसे में यदि इसी प्रक्रिया से जुड़ी किसी गंभीर शिकायत पर महीनों तक प्रभावी जांच न हो और विभाग अपने ही रिकॉर्ड की पड़ताल करने के बजाय शिकायतकर्ता से ही साक्ष्य मांगने लगे,तो स्वाभाविक रूप से कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं,ऐसा ही एक मामला तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितीश कुमार मिश्रा से जुड़ा सामने आया है,शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री के सूरजपुर दौरे के दौरान भोजन परीक्षण दल में एक ऐसे व्यक्ति को'नमूना सहायक' के रूप में शामिल किया गया, जो कथित रूप से विभाग का अधिकृत नमूना सहायक था ही नहीं, यदि यह आरोप सही साबित होता है तो यह केवल विभागीय अनियमितता नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय हो सकता है।

बता दे की जब देश के प्रधानमंत्री के भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच से जुड़े प्रकरण पर ही गंभीर सवाल उठ रहे हों, तब स्वाभाविक रूप से अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के लिए होने वाले खाद्य परीक्षण की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में आ जाती है,यदि इतने संवेदनशील मामले में प्रकाशित समाचारों, उपलब्ध दस्तावेजों और शिकायतों के बावजूद सक्षम स्तर पर निष्पक्ष जांच तक नहीं हो,तो यह केवल एक शिकायत का विषय नहीं रह जाता,बल्कि विभागीय जवाबदेही और कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है,रायपुर से प्रकाशित कई प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में यह मामला फोटो और दस्तावेजों के साथ प्रमुखता से प्रकाशित हुआ,इसके बावजूद यदि विभाग ने तथ्यों का सत्यापन कर स्पष्ट निष्कर्ष सामने नहीं रखा,तो संबंधित अधिकारी की पहुंच,प्रभाव अथवा उसे प्राप्त संरक्षण को लेकर भी स्वाभाविक रूप से चर्चाएं और सवाल उठना लाजिमी हैं, ऐसे मामलों में सच्चाई सामने लाने का सबसे प्रभावी माध्यम निष्पक्ष,पारदर्शी और समयबद्ध जांच ही हो सकती है।

सबसे आसान जांच थी,लेकिन वही नहीं हुई-इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शिकायत की पुष्टि के लिए किसी जटिल जांच की आवश्यकता नहीं थी,विभाग केवल अपने रिकॉर्ड देखकर यह स्पष्ट कर सकता था कि क्या सुमित त्रिपाठी विभाग का नियमित नमूना सहायक था? यदि नहीं था,तो उसका नाम आदेश में किस आधार पर दर्ज किया गया? किस अधिकारी ने उसका नाम प्रस्तावित किया? क्या उसके पास अधिकृत पहचान पत्र था? ये सभी तथ्य विभागीय अभिलेखों से आसानी से सत्यापित किए जा सकते थे।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा था मामला-प्रधानमंत्री के किसी भी दौरे में भोजन परीक्षण प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है,इस प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का सत्यापन तथा अधिकृत होना महत्वपूर्ण होता है, यदि किसी अनधिकृत व्यक्ति की मौजूदगी संबंधी शिकायत सामने आती है,तो सामान्यतः उसकी गंभीर जांच अपेक्षित मानी जाती है,यही कारण है कि इस शिकायत को सामान्य विभागीय विवाद के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संभावित प्रशासनिक प्रश्न के रूप में देखा जा रहा है।

नितीश कुमार मिश्रा पहले भी रहे हैं विवादों में-तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितीश कुमार मिश्रा का नाम पूर्व में भी विभिन्न शिकायतों में सामने आता रहा है,उपलब्ध शिकायत पत्र में उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार, अवैध वसूली,पद के दुरुपयोग तथा विभागीय जांच की मांग की गई है,हालांकि इन आरोपों की पुष्टि सक्षम जांच के बाद ही हो सकती है।

सूत्रों के दावे भी जांच के दायरे में...

सूत्रों का दावा है कि सूरजपुर में पदस्थापना के दौरान नितीश कुमार मिश्रा विभागीय स्थानांतरण,पदस्थापन और प्रयोगशाला से जुड़े मामलों में प्रभाव रखते थे,यह भी आरोप लगाए जाते रहे हैं कि वे कुछ व्यक्तियों को नमूना सहायक के रूप में स्थापित कराने का प्रयास करते रहे,इसी प्रकार कुछ सूत्र यह भी दावा करते हैं कि वे निजी वाहन पर सायरन का उपयोग करते थे, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इनकी जांच होना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री के दौरे के लिए बना था विशेष भोजन परीक्षण दल

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार 5 नवंबर 2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,सूरजपुर द्वारा प्रधानमंत्री के प्रस्तावित 7 नवंबर 2023 के दौरे के लिए भोजन परीक्षण दल का गठन किया गया,इस आदेश में चिकित्साधिकारी के साथ तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितीश कुमार मिश्रा तथा सुमित त्रिपाठी को'नमूना सहायक'के रूप में शामिल किया गया था,यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है।

शिकायत में क्या लगाए गए आरोप?

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आदेश में जिस सुमित त्रिपाठी को नमूना सहायक बताया गया,वह विभाग का अधिकृत नमूना सहायक नहीं था, शिकायत के अनुसार एक निजी व्यक्ति को सरकारी व्यवस्था के भीतर प्रवेश दिलाकर भोजन परीक्षण प्रक्रिया में शामिल कराया गया,यदि शिकायत सही साबित होती है तो कई गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं क्या भोजन परीक्षण टीम में किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश मिला? यदि हां,तो किसकी अनुमति से? क्या सुरक्षा एजेंसियों को सही जानकारी उपलब्ध कराई गई थी? क्या सरकारी आदेश में गलत विवरण दर्ज किया गया?

लेकिन विभाग ने शिकायतकर्ता को ही बुला लिया-

शिकायत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तक पहुंची, इसके बाद 19 जनवरी 2026 को उप सचिव विजय कुमार चौधरी द्वारा शिकायतकर्ता को पत्र जारी कर कहा गया कि शिकायत के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और उन्हें निर्धारित तिथि पर दस्तावेजों सहित उपस्थित होना होगा, यहीं से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

जब रिकॉर्ड विभाग के पास था तो शिकायतकर्ता से सबूत क्यों?-

आलोचकों का तर्क है कि यदि विवाद सरकारी आदेश में दर्ज एक नाम का था, तो उसकी जांच करने का अधिकार और दायित्व स्वयं विभाग का था, सबसे पहले विभाग यह देख सकता था क्या संबंधित व्यक्ति कर्मचारी था? उसका नियुक्ति आदेश क्या था? उसका सेवा रिकॉर्ड क्या कहता है? क्या वह वास्तव में नमूना सहायक के रूप में अधिकृत था? यदि इन प्रश्नों के उत्तर रिकॉर्ड से मिल सकते थे, तो शिकायतकर्ता से अतिरिक्त साक्ष्य मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यही प्रश्न अब पूरे मामले का केंद्र बन गया है।

अब सवाल सिर्फ एक अधिकारी का नहीं...

पूरा मामला अब केवल नितीश कुमार मिश्रा तक सीमित नहीं रह गया है,अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या उप सचिव स्तर पर प्रारंभिक तथ्य सत्यापन किया गया? क्या विभाग ने अपने ही अभिलेखों की जांच की? क्या शिकायत को केवल पत्राचार तक सीमित कर दिया गया? यदि आदेश में दर्ज नाम संदिग्ध था तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? क्या इतने गंभीर मामले में स्वतंत्र जांच बैठाई जाएगी?

- पीएम की सुरक्षा में कथित चूक के आरोप,फिर भी जांच नहीं!
- 'नमूना सहायक' के नाम पर निजी व्यक्ति को ले जाने की शिकायत,कार्रवाई के बजाय साक्ष्य मांगता रहा विभाग
- प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला या फाइलों में दबा सच? सरकारी आदेश में दर्ज नाम की जांच तक नहीं हुई, आखिर किसका संरक्षण?
- पीएम के भोजन परीक्षण दल में कथित अनधिकृत व्यक्ति की शिकायत पर उठे गंभीर सवाल...
- जब विभाग ही अपने आदेश नहीं पढ़ेगा, तो सच सामने कैसे आएगा?
- पीएम सुरक्षा प्रकरण में प्रारंभिक जांच तक नहीं, सवालों के घेरे में जिम्मेदार अधिकारी
- सरकारी आदेश में दर्ज 'नमूना सहायक' की सत्यता पर आज तक नहीं खुला राज...

सबकी निगाह अब सरकार पर...

यह मामला केवल एक शिकायत या एक अधिकारी का नहीं,बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और संवेदनशील सरकारी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता से जुड़ा है,यदि शिकायत निराधार है तो विभाग को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए,लेकिन यदि शिकायत में तथ्य पाए जाते हैं,तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होना भी उतना ही आवश्यक है,देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च होनी चाहिए,ऐसे मामलों में समयबद्ध, निष्पक्ष और दस्तावेज़ आधारित जांच ही जनता का विश्वास बनाए रख सकती है।

अगले अंक में पढ़िए...नौकरी में आने के बाद कहाँ-कहाँ खरीदी गई संपत्तियां? दस्तावेज़ों के साथ विशेष खुलासा।

सिंघत में विकास की राशि बनी 'एटीएम'!

निर्माण कार्यों में लाखों रुपये खर्च होने का दावा, कई काम अधूरे तो कई का धरातल पर नहीं मिला नामोनिशान

खबर प्रकाशित होने के बाद भी कार्रवाई नहीं, ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

-संवाददाता-

खड़गवां,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जनपद पंचायत खड़गवां अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंघत में विकास कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है,ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में विकास के नाम पर लाखों रुपये की राशि खर्च दिखाई गई,लेकिन कई कार्य आज भी अधूरे हैं,जबकि कुछ कार्यों का धरातल पर कोई अस्तित्व ही दिखाई नहीं देता,मामले में पहले भी समाचार प्रकाशित होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में असंतोष है।

पूर्व और वर्तमान कार्यकाल दोनों पर उठे सवाल-ग्रामीणों का कहना है कि कथित अनियमितताएं केवल एक कार्यकाल तक सीमित नहीं हैं,उनके अनुसार पूर्व सरपंच के कार्यकाल में शुरू हुई गड़बड़ियों का सिलसिला वर्तमान पंचायत कार्यकाल में भी जारी है, आरोप है कि पंचायत में मूलभूत सुविधा मद,15 वें वित्त आयोग तथा अन्य योजनाओं की राशि का उपयोग नियमानुसार नहीं किया गया, कई कार्यों के लिए राशि आहरित होने के बावजूद निर्माण अधूरा है या मौके पर उसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल रहा।

गांव का विकास नहीं,जिम्मेदारों का विकास हुआ:- ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में विकास कार्यों की अपेक्षा जिम्मेदारों के आर्थिक हित अधिक साधे गए। उनका कहना है कि पिछले कई वर्षों में गांव में अपेक्षित विकास नहीं हुआ,जबकि सरकारी योजनाओं के नाम पर लगातार राशि खर्च होने का रिकॉर्ड मौजूद है, इससे ग्रामीणों के बीच पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

कार्रवाई नहीं होने से बढ़ रहे संदेह-ग्रामीणों का कहना है कि कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायतें और समाचार प्रकाशित होने के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है,कुछ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा यह कहा जाता है कि शिकायतों और खबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता तथा जांच भी उनके पक्ष में ही हो जाती है। हालांकि,इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

विश्व आदिवासी दिवस 2026 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न

9 अगस्त को होगा जिला स्तरीय भव्य आयोजन,समाज की संस्कृति,परंपरा और एकता को मिलेगा नया आयाम

-संवाददाता-

मनेंद्रगढ़ (एमसीबी),03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

आगामी 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस 2026 के जिला स्तरीय आयोजन की तैयारियों को लेकर सर्व आदिवासी समाज, जिला एमसीबी के तत्वावधान में गोंडवाना भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, बैठक में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों,जनप्रतिनिधियों, युवाओं एवं समाजजनों ने भाग लेकर आयोजन को भव्य,गरिमामय और ऐतिहासिक बनाने के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की। बैठक में पूर्व विधायक गुलाब कमरो, जिला संरक्षक परमेश्वर गुरुजी, जिला अध्यक्ष शरण सिंह,आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमोल सिंह मरावी,अमर सिंह,भगवान सिंह सहित समाज के अनेक

वरिष्ठ पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे, सभी ने विश्व आदिवासी दिवस को समाज की सांस्कृतिक पहचान और एकता का प्रतीक बताते हुए आयोजन को व्यापक स्वरूप देने पर सहमति व्यक्त की, बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष का आयोजन केवल उत्सव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आदिवासी समाज की गौरवशाली संस्कृति, परंपराओं,इतिहास, भाषा, लोककला,लोकजीवन एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति जनजागरूकता का माध्यम भी बनेगा,कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां,पारंपरिक वेशभूषा,सामाजिक संदेशों पर आधारित आयोजन और समाज की विभिन्न उपलब्धियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा।

सभी वर्गों की भागीदारी पर रहेगा विशेष जोर...

बैठक में समाज के युवाओं, महिलाओं,छात्र-छात्राओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया,आयोजन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभिन्न समितियों के गठन,जिम्मेदारियों के निर्धारण,प्रचार-प्रसार,स्वागत व्यवस्था,सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। संस्कृति संरक्षण का दिया संदेश-वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज सदियों से प्रकृति संरक्षण,सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों का संवाहक रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से समाज की एकता,पहचान और अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा,पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराएं देश की अमूल्य धरोहर हैं। उनका संरक्षण और संवर्धन समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है,उन्होंने जिले के सभी समाजजनों से 9 अगस्त को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया,बैठक के अंत में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने जिले के सभी समाजजनों,युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की,ताकि समाज की एकता,संस्कृति और गौरव का संदेश व्यापक स्तर तक पहुंच सके।

जिला बने तीन साल,फिर भी शिक्षा विभाग के 35 पदों का सेटअप नहीं

पूर्व महापौर के. डोमरु रेड्डी ने सीएम पोर्टल पर की शिकायत,कहा...स्टाफ की कमी से चरमराई एमसीबी जिले की शैक्षणिक व्यवस्था

-संवाददाता-

चिरमिरी,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

नवगठित मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिला बने तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग के आवश्यक पदों का सेटअप स्वीकृत नहीं होने का मुद्दा अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है, चिरमिरी नगर निगम के पूर्व महापौर एवं जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के. डोमरु रेड्डी ने इस संबंध में सीएम पोर्टल 1076 पर शिकायत दर्ज कराते हुए स्कूल

शिक्षा विभाग के 35 आवश्यक पदों के सेटअप को तत्काल स्वीकृत करने की मांग की है, उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण पद आज भी स्वीकृत नहीं किए गए हैं, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। उनका दावा है कि इसका असर जिले के परीक्षा परिणामों पर भी दिखाई दे रहा है।

जिला बना,लेकिन शिक्षा विभाग का ढांचा अधूरा-के. डोमरु रेड्डी ने कहा कि जब एमसीबी जिले का गठन हुआ,तब विकास और प्रशासनिक सुविधाओं को लेकर लोगों में उत्साह था, लेकिन शिक्षा विभाग के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक व्यवस्था पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप आज भी जिला शिक्षा कार्यालय आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों के अभाव में कार्य कर रहा है, उनका कहना है कि स्थायी व्यवस्था नहीं होने से विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और विद्यालयों की निगरानी, शैक्षणिक गुणवत्ता तथा प्रशासनिक कार्यों पर भी असर पड़ रहा है।

35 महत्वपूर्ण पद अब भी स्वीकृति की प्रतीक्षा में-शिकायत के अनुसार,एमसीबी जिले में जिला शिक्षा अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक संचालक, सहायक परियोजना अधिकारी, एमआईएस प्रशासक, सर्व शिक्षा डीएमसी,लेखापाल, एडीपीओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा सहायक ग्रेड-1,2 एवं 3 सहित लगभग 35 पदों का नियमित सेटअप अब तक स्वीकृत नहीं किया गया है,पूर्व महापौर का कहना है कि इन पदों के अभाव में कई कार्य अस्थायी व्यवस्थाओं के सहारे संचालित किए जा रहे हैं।

परीक्षा परिणाम पर भी उठाए सवाल-के. डोमरु रेड्डी ने दावा किया कि जिला बनने के बाद से लगातार तीन वर्षों तक एमसीबी जिले का परीक्षा परिणाम राज्य की सूची में अंतिम पायदान पर रहा है, उनके अनुसार यह स्थिति शिक्षा विभाग में पर्याप्त अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी का परिणाम हो सकती है,उन्होंने सवाल उठाया कि यदि शिक्षा विभाग का प्रशासनिक ढांचा ही पूर्ण नहीं होगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर परीक्षा परिणाम की अपेक्षा कैसे की जा सकती है।

अस्थायी व्यवस्थाओं पर जताई आपत्ति-पूर्व महापौर ने आरोप लगाया कि स्थायी सेटअप स्वीकृत नहीं होने के कारण कई पदों पर अस्थायी रूप से कर्मचारियों की पदस्थापना की गई है।

सावन में मनोरंजन की बाढ़,7 से 28 अगस्त तक बड़े पर्दे पर रिलीज हो रहीं 12 बड़ी फिल्में

इस महीने सिनेमाघरों में एक्शन, रोमांस और हॉरर,हर तरह का मनोरंजन देखने को मिलेगा...

जुलाई के महीने में भले ही सिनेमाघरों में ज्यादा फिल्में न उतरी हों,लेकिन अगस्त का महीना गुलजार होने वाला है। 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक... इस साल की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं।

इस महीने सिनेमाघरों में एक्शन,रोमांस और हॉरर फिल्मों का कहर बरपने वाला है। बॉक्स ऑफिस पर जून और जुलाई का सूखा अब अगस्त में रिलीज होने वाली फिल्में खत्म करेंगी।

डीसी

निर्देशन में अपनी काबिलियत दिखाने वाले लोकेश कनगराज फिल्म डीसी से अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं। वह देवदास नॉवेल से प्रेरत फिल्म डीसी की कहानी देवदास और चंद्रा की है जो एक खतरनाक दुनिया में कदम रखते हैं।

जॉनर- रोमांटिक एक्शन
रिलीज डेट- 7 अगस्त
स्टार कास्ट- लोकेश कनगराज, वामिका गब्बी, संजना कृष्णमूर्ति

जी.डी.एन

गोपालस्वामी दोराईस्वामी नायडू उर्फ भारत का एडिसन से प्रेरित फिल्म जी.डी.एन आर माधवन की अपकमिंग फिल्म है। इस फिल्म में गोपालस्वामी की ताकतवर विरोधी ताकतों के खिलाफ संघर्षों और इनोवेशन के सफर को दिखाया जाएगा।

जॉनर- बायोग्राफिकल ड्रामा
रिलीज डेट- 7 अगस्त
स्टार कास्ट- आर माधवन, सत्यराज, जयराम, प्रियामणि

ओह माय डॉग

पंकज त्रिपाठी की आगामी फिल्म ओह माय डॉग की कहानी इंसानों और कुत्तों के बीच वफादारी, प्यार और जिंदा रहने की जद्दोजहद के गहरे रिश्तों पर आधारित फिल्म है।

जॉनर- एडवेंचर ड्रामा
रिलीज डेट- 7 अगस्त
स्टार कास्ट-पंकज त्रिपाठी,पवन मल्होत्रा,माही राय

आवारापन 2

19 साल बाद आवारापन का सीक्वल आ रहा है। फिल्म में फिर से शिवम के किरदार में इमरान हाशमी की वापसी होगी जो जुर्म की दुनिया में प्रायश्चित, प्यार और त्याग का मुश्किल सफर होगा।

जॉनर- एक्शन रोमांस
रिलीज डेट- 14 अगस्त
स्टार कास्ट- इमरान हाशमी,दिशा पाटनी, सलिल आचार्य,शबाना आजमी

बंटवारा 1947

साल की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों में एक नाम बंटवारा 1947 का भी है। इस फिल्म की कहानी भारत का बंटवारा और बिखरे हुए परिवार की उथल-पुथल भरी जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है।

जॉनर- पीरियड एक्शन ड्रामा
रिलीज डेट- 14 अगस्त
स्टार कास्ट- सनी देओल, प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी

अगाधा

अगर आप एक्शन या रोमांस को छोड़ हॉरर फिल्में देखने की सोच रहे हैं तो अगाधा देख सकते हैं। यह कहानी कई दुःखद और रहस्यमयी मौतों के इर्द-गिर्द घूमती है।

जॉनर- मिस्ट्री सुपरनैचुरल थ्रिलर
रिलीज डेट- 14 अगस्त
स्टार कास्ट- कामाक्षी भास्करला, उल्का गुप्ता, श्रवण रेड्डी

विश्वनाथ एंड संस

संजय विश्वनाथ ने एक इंटरनेशनल शूटर के तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने में दशकों बिताए हैं। मगर अब वह अपनी जिंदगी जीने के तरीके को बदलने की ओर आगे बढ़ता है।

जॉनर- फैमिली ड्रामा
रिलीज डेट- 14 अगस्त
स्टार कास्ट- सूर्या, ममिता बैजू, राधिका सरतकुमार

आईएम गेम

एक निडर जुआरी जो जिंदगी से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करता है,अचानक ऐसी घटनाओं में फंस जाता है जो उसकी दुनिया को उलट-पुलट कर देती हैं।

जॉनर- फैंटेसी थ्रिलर
रिलीड डेट- 20 अगस्त
स्टार कास्ट- दुलकर सलमान, समय

द पैराडाइज

नानी की मोस्ट अवेटेड फिल्म द पैराडाइज 1980 के दशक में सेट जनजाति भेदभाव और नागरिकता के लिए संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म को लेकर काफी इंतजार हो रहा था।

जॉनर- एक्शन थ्रिलर
रिलीज डेट- 21 अगस्त
स्टार कास्ट- नानी, सोनाली कुलकर्णी, मोहन बाबू

इंसिडियस : आउट ऑफ द फर्दर

इनसिडियस- द रेड डोर का सीक्वल और इनसिडियस फ्रैंचाइजी की छठी फिल्म इंसिडियस : आउट ऑफ द फर्दर फिर से सिनेमाघरों में दहशत फैलाने आ रहा है। फिल्म में बुरी शक्तियों के चंगुल में फंसने वाली लड़की की कहानी दिखाई जाएगी।

जॉनर- सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर

रिलीज डेट- 21 अगस्त
स्टार कास्ट- लिन शेय, अमेलिया ईव

टॉक्सिक

केजीएफ के बाद अब गोवा में राज यश राज करने आ रहे हैं। टॉक्सिक में उनका किरदार राया धोखे और खून-खराबे के जरिए शहर के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा जमाता है, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

जॉनर- एक्शन थ्रिलर
रिलीज डेट- 26 अगस्त
स्टार कास्ट- यश, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयनतारा, हुमा कुरैशी

ईथा

मराठी तमाशा और लावणी की मशहूर कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर पर बेस्ड फिल्म ईथा को लेकर भी काफी बज है।

जॉनर- बायोग्राफिकल ड्रामा
रिलीज डेट- 28 अगस्त
स्टार कास्ट- श्रद्धा कपूर, रणदीप हुड्डा, नाना पाटेकर

अगस्त के महीने में राजकुमार राव की फिल्म प्रहार भी रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है।

काम के प्रति गजब का समर्पण : 20 घंटे शूट के बाद भी रुकीं नहीं कीर्ति सुरेश

एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट पोस्ट के ज़रिए अपने इंस्टाग्राम फ़ैमिली को अपनी बिज़ी लेकिन संतोषजनक वर्क लाइफ़ की एक झलक दिखाई। नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली एक्ट्रेस ने बताया कि वह लगातार 20 घंटे से काम कर रही थीं और तुरंत ही अपने अगले शूट के लिए निकल रही थीं। कीर्ति ने अपने ऑफ़िशियल इंस्टाग्राम हैंडल के स्टोरीज़ सेक्शन में लिखा, कल इसे पोस्ट करने की हिम्मत नहीं थी... एक शूट से दूसरे शूट पर भाग रही थी। उफ़!!! आख़िरकार सोने से पहले मैं 41 घंटे तक जागी रही। हालांकि,कीर्ति ने कहा कि वह काम के इस ज़बरदस्त शेड्यूल को एक वरदान मानती हैं। महानटी एक्ट्रेस को अपने इंस्टाग्राम क्लिप में यह कहते हुए सुना गया,अभी-अभी अपने कमरे में आई हूँ, सचमुच 24 घंटे बाद,लगभग 20 घंटे काम किया। मैं कल सुबह 6 बजे निकली थी और अभी भी सुबह के 6 बजे हैं और बात यह है कि मैं एक घंटे में अपने अगले काम के लिए निकल रही हूँ। शिकायत करने के लिए अच्छी परेशानियाँ हैं,ज़िंदगी ऐसी ही है,है ना? मैं इसे एक वरदान मानती हूँ, ज़िंदगी के नाम।

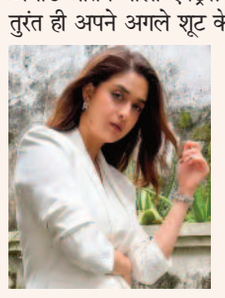

इसके बाद, कीर्ति ने एक मज़ेदार मिरर सेल्फ़ी भी अपलोड की। उन्होंने मज़ाक में यह भी कहा कि सिर्फ़ एक घंटे का ब्रेक मिलने के बाद भी, वह दोबारा काम पर जाने से पहले सेल्फ़ी लेने के लिए हिम्मत जुटा पाईं। तस्वीर पर लिखे टेक्स्ट में कहा गया,एक घंटे बाद। निकलने से पहले मुझमें मिरर सेल्फ़ी लेने की हिम्मत थी। अपनी सबसे हालिया पोस्ट में, कीर्ति को एक और शूट के लिए निकलते हुए देखा गया। वह चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ चल रही थीं। दसारा एक्ट्रेस ने वीडियो में कहा, और अब शूट के लिए निकल रही हूँ, आज इस टी-शर्ट का सच में कुछ मतलब है,उन्होंने अपनी आई विल सर्विव (मैं बच जाऊँगी) लिखी टी-शर्ट की ओर इशारा किया। कीर्ति ने बात खत्म करते हुए कहा, हाँ, मैं बच जाऊँगी। अपने प्रोफ़ेशनल कामों की बात करें तो, कीर्ति के कई अच्छे प्रोजेक्ट्स रिलीज़ होने वाले हैं,जैसे सत्यवान सावित्री,रफ़्तार,अक्का और राउडी जनार्दन।

स्टंट बना विवाद, गौरव खन्ना की चोटों पर सवाल

टेलीविजन के चर्चित स्टंट रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में एक स्टंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शो के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना ने अपनी पीठ पर आए दर्दनाक निशानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिसके बाद कई दर्शकों ने स्टंट की कठिनाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। 'खतरों के खिलाड़ी' अपनी खतरनाक चुनौतियों और रोमांचक स्टंट के लिए जाना जाता है। शो में कंटेस्टेंट्स को डर, शारीरिक क्षमता और मानसिक मजबूती की परीक्षा लेने वाले टास्क दिए जाते हैं। हालांकि, हालिया एपिसोड में दिखाए गए एक स्टंट के बाद कुछ दर्शकों का कहना है कि चुनौती और जोखिम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। गौरव खन्ना ने शेयर की चोटों की तस्वीरें कंटेस्टेंट गौरव खन्ना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी पीठ की तस्वीरें साझा कीं, जिनमें स्टंट के बाद आए निशान दिखाई दे रहे थे। तस्वीरों के सामने आने के बाद फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं। कई यूजर्स ने चिंता जताई कि मनोरंजन के लिए किए जाने वाले स्टंट में कंटेस्टेंट्स की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या स्टंट की कठिनाई को तय करते समय सुरक्षा मानकों का पर्याप्त ध्यान रखा गया था। गौरव खन्ना की तस्वीरों के बाद सोशल मीडिया पर शो के निर्माताओं को लेकर बहस शुरू हो गई। कुछ यूजर्स ने आरोप लगाया कि स्टंट को रोमांचक बनाने के प्रयास में इसे जरूरत से ज्यादा कठिन बना दिया गया। कुछ टिप्पणियों में दर्शकों ने कहा कि शो का उद्देश्य चुनौती देना है, लेकिन कंटेस्टेंट्स को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति नहीं बननी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने इस स्टंट को टॉर्चर जैसा बताया और निर्माताओं से जवाबदेही की मांग की।

खेल समाचार

सीडब्ल्यूजी 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर राष्ट्रपति मुर्मू ने जताई खुशी

नई दिल्ली,03 अगस्त 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की टीम के शानदार प्रदर्शन की तारीफ़ की। उन्होंने महिला खिलाड़ियों के योगदान पर खास ज़ोर दिया, जिन्होंने देश के 13 गोल्ड मेडल में से आठ जीते।

राष्ट्रपति भवन ने एक पोस्ट में राष्ट्रपति की खुशी ज़ाहिर की और सभी 39 मेडल जीतने वालों और टीम के सदस्यों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, मुझे खुशी है कि भारत के खिलाड़ियों ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया है। मुझे यह देखकर खास खुशी हो रही है कि महिलाओं ने भारत के लिए जीते गए 13 गोल्ड मेडल में से 8 मेडल हासिल किए हैं।

उन्होंने आगे कहा, सभी 39 मेडल जीतने वालों और टीम के हर उस सदस्य को मेरी तरफ़ से बहुत-बहुत बधाई, जिन्होंने इन खेलों में योगदान दिया। राष्ट्रपति ने यह भरोसा भी जताया कि भारत के खिलाड़ी भविष्य में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में और भी बड़ी सफलता हासिल करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा,मुझे यकीन है कि भारत के खिलाड़ी भविष्य के अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में देश का नाम और रोशन करेंगे। 11 दिनों तक चली प्रतियोगिताओं के बाद 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हुआ। एक शानदार समापन समारोह में स्कॉटलैंड ने औपचारिक रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स का झंडा और सेरेमोनियल बैटन भारत को सौंपा, जो 2030 में होने वाले ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण का मेज़बान है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही भारत, ऑस्ट्रेलिया के बाद एक से ज़्यादा बार इस मल्टी-स्पोर्ट इवेंट की मेज़बानी करने वाला दूसरा देश बन जाएगा।

सीडब्ल्यूजी सिल्वर विजेता हरजिंदर और ज्ञानेश्वरी की नजर 2030 में घरेलू गोल्ड पर

नई दिल्ली,03 अगस्त 2026। हाल ही में ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर और ज्ञानेश्वरी यादव ने 2030 में होने वाले अगले गेम्स में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का संकल्प लिया है। ये गेम्स अहमदाबाद में भारत में ही आयोजित होंगे।

सीडब्ल्यूजी 2026 में भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम ने कुल आठ मेडल जीते, जिनमें एक गोल्ड, छह सिल्वर और एक ब्रॉन्ज़ मेडल शामिल था। सबसे खास बात मीराबाई चानू का महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीतना रहा, जिससे उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की हैट्रिक पूरी की। महिलाओं के 53 किग्रा वर्ग में ज्ञानेश्वरी यादव का नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाला प्रदर्शन (स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कुल 199 किग्रा वज़न उठाकर सिल्वर मेडल जीता) और +110 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडलिस्ट लवप्रीत सिंह का स्नैच में नेशनल रिकॉर्ड (176 किग्रा) बनाना भी खास रहा। ऋषिकंता सिंह (पुरुष 60 किग्रा), मुथुपंडी राजा (पुरुष 65 किग्रा), अजय बाबू (पुरुष 79 किग्रा) और हरजिंदर कौर (महिला 69 किग्रा) का सिल्वर मेडल और बिंद्यारानी देवी (महिला 58 किग्रा) का ब्रॉन्ज़ मेडल जीतना भी शानदार प्रदर्शन रहा।

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा आयोजित स्वागत और सम्मान समारोह के दौरान बात करते हुए, हरजिंदर ने अपना मेडल अपने परिवार और कोचों को समर्पित किया, जिन्होंने उन्हें इस मुकाम

तक पहुँचने में मदद की। 2022 के गेम्स में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने के बाद ग्लासगो में सिल्वर मेडल जीतकर अपना प्रदर्शन बेहतर करने वाली हरजिंदर का अगला लक्ष्य भारत में गोल्ड मेडल जीतना है। सबसे पहले, मैं यह मेडल अपने परिवार को समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि इस मुकाम तक पहुँचने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और फिर, वे लोग जिन्होंने मुझे इस खेल से जोड़ा - मेरे कोच परमजीत शर्मा और जसपाल सिंह। उन्होंने हमेशा मेरी तारीफ़ की और मेरा हौसला बढ़ाया। मैं उनके प्रति अपना गहरा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था, और इस बार मैंने सिल्वर मेडल जीता है। अगली बार, मेरा लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतना होगा, खासकर इसलिए क्योंकि ये गेम्स भारत में होने वाले हैं।

17 वर्षीय तन्वी शर्मा चैंपियन बनकर रचा इतिहास

भावुक होकर कोच को पहनाया अपना गोल्ड मेडल

ताइपे,03 अगस्त 2026। भारतीय बैडमिंटन की उभरती हुई युवा स्टार तन्वी शर्मा ने रविवार को एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। पंजाब की रहने वाली महज 17 साल की इस होनहार खिलाड़ी ने ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के विमेंस सिंगल्स का खिताब जीतकर पूरी दुनिया में देश का डंका बजा दिया है। यह उनके करियर का पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब है। खिताबी मुकाबले में तन्वी ने अपने तूफानी और आक्रामक खेल के दम पर वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी थुय लिन गुयेन को सीधे गेमों में 21-16, 21-16 से बुरी तरह धो डाला। यह खिताबी मुकाबला केवल 36 मिनट तक चला। इस शानदार और एकतरफा जीत के साथ ही तन्वी ताइपे ओपन का खिताब जीतने वाली इतिहास की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी (पुरुष या महिला) बन गई हैं।

न्यायालय तहसीलदार एवं दण्डाधिकारी भटगांव ,तहसील भटगांव,जिला-सूरजपुर

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./ब-121/2025-26

आम जनता ग्राम अनरोखा को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्यामलाल राजवाड़े आ0 धनुषधारी राजवाड़े जाति रजवार निवासी ग्राम अनरोखा तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर द्वारा अपने माता कुलमेत का जन्म/मृत्यु दिनांक 08/12/2025 को जन्म/मृत्यु होने पर आवेदक द्वारा अपने माता का मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत शुल्क अदा कर चालान की प्रति, शपथ पत्र अनुपलब्धतां प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्यवाही आरंभ कर दी गयी है।

जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आक्षेप हो तो वह अपना आक्षेप दिनाक 05/08/2026 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं तदनुसार कार्यवाही कर दी जायेगी।

आज दिनांक 22/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुदा से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भटगांव
जिला-सूरजपुर,छ0ग0

सील

न्यायालय तहसीलदार पटना जिला-कोरिया,छत्तीसगढ़

रा.प्र.क्र./ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा समस्त ग्रामीण जनता ग्राम कटकोना को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ आवेदिका अंकित सिंह आ0/पति अनिल सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम कटकोना थाना पटना तहसील पटना जिला कोरिया के द्वारा आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पुत्र/पुत्री स्वम के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंधी (EWS प्रमाण पत्र) आय प्रमाण पत्र प्रदाय किया जावे। आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र अंकसूची, बी-1 की छायाप्रति संलग्न किया है। अतः जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को उक्त प्रमाण पत्र जारी करने से कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से दिनांक 15 /08/2026 तक उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। तदनुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

आज दिनांक 30/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
पटना,जिला-कोरिया,छ0ग0

सील

न्यायालय तहसीलदार एवं दण्डाधिकारी भटगांव ,तहसील भटगांव,जिला-सूरजपुर

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./ब-121/2025-26

आम जनता ग्राम चुनगड़ी को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेन्द्र कुमार मिंज आ0 सुखी राम जाति उरांव निवासी ग्राम चुनगड़ी तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर द्वारा अपने राजेन्द्र का जन्म दिनांक 10/06/1989 को जन्म/मृत्यु होने पर आवेदक द्वारा अपने स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत शुल्क अदा कर चालान की प्रति, शपथ पत्र अनुपलब्धतां प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्यवाही आरंभ कर दी गयी है।

जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आक्षेप हो तो वह अपना आक्षेप दिनाक 11/08/2026 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं तदनुसार कार्यवाही कर दी जायेगी।

आज दिनांक 28/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुदा से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भटगांव
जिला-सूरजपुर,छ0ग0

सील

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ आवेदिका दिनेश गुप्ता आ0/पति सी0पी0गुप्ता जाति, निवासी कम्पनी बाजार अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला - कम्पनी बाजार, शीट नम्बर-3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1306/4853 रकबा 0.32 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 17.08.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 31.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

सील

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र./ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दिनेश शरण मिश्रा पिता स्व.गार्गी मिश्रा व अन्य मुख्तार आम द्वितेन्द्र कुमार मिश्रा आ. जीवन नाथ मिश्रा निवासी किसान राईस मिल विवेकानंद वार्ड नंबर 11 तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की व्यपवर्तित भूमि ग्राम नमनाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 2/1051 रकबा 0.020 हे0 भूमि को अनावेदक द्वितेंन्द्र कुमार मिश्रा आ0 जीवननाथ मिश्रा निवासी विवेकानंद नगर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास निजी कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के कारण अंकन राशि 7,00,000/- में सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुंजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 10.08.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते । समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 17/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

तहसीलदार
अंबिकापुर,सरगुजा

सील

C M Y K

'स्वास्थ्य व्यवस्था केवल इलाज नहीं, बल्कि समय पर जांच, गुणवत्तापूर्ण उपचार और जीवन बचाने की व्यवस्था है : स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल

आयुष्मान योजना में देश में प्रथम स्थान का दावा, आधुनिक जांच सुविधाओं और खाद्य सुरक्षा पर सरकार का विशेष जोर

रायपुर,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
प्रेस वार्ता के तीसरे चरण में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था, कैंसर एवं किडनी रोगियों के उपचार,आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धियों,जांच सुविधाओं के विस्तार तथा दवा एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल अस्पताल बनाना नहीं बल्कि ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार करना है,जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को भी समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध हो सके।

अब जिला स्तर पर भी कैंसर मरीजों को मिलेगी राहत

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले कैंसर का इलाज बड़े शहरों तक सीमित था,मरीजों को रायपुर या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था,जिससे समय और धन दोनों की भारी हानि होती थी,इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 26 जिलों में 'डे-केयर कीमोथेरेपी सेंटर' शुरू किए हैं, उन्होंने बताया कि–अब मरीजों को सामान्य कीमोथेरेपी के लिए राजधानी आने की आवश्यकता नहीं होगी, जिला अस्पतालों में ही उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है,इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, समय पर उपचार मिलने से कैंसर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा,मंत्री ने इसे प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक बताया।

डायलिसिस सुविधा का पूरे प्रदेश में विस्तार

उन्होंने कहा कि जीवनशैली में बदलाव और बढ़ते मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप के कारण किडनी रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसी को देखते हुए सरकार ने 32 जिलों में निशुल्क डायलिसिस सेवा शुरू कर दी है,शेष 33वें जिले में भी यह सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, इसके अलावा 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक भी डायलिसिस सुविधा का विस्तार किया जा रहा है,मंत्री ने कहा कि अब गरीब मरीजों को निजी अस्पतालों में भारी खर्च नहीं उठाना पड़ेगा।

108 एम्बुलेंस सेवा को मिली नई ताकत–स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क का विस्तार किया गया,उन्होंने बताया कि–पहले 108 एम्बुलेंस की संख्या 300 से भी कम थी,वर्तमान में इसे बढ़ाकर 375 कर दिया गया है, साथ ही एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाई गई,गंभीर मरीजों को बेहतर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।

नवजात शिशुओं के लिए विशेष एम्बुलेंस–मंत्री ने बताया कि नवजात शिशुओं को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाने के लिए विशेष नियोनेटल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है,उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जहां इस प्रकार की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई,पांच अत्याधुनिक नियोनेटल एम्बुलेंस सभी संभागीय मुख्यालयों में तैनात की गई हैं, इनमें नवजात शिशुओं के लिए विशेष जीवनरक्षक उपकरण उपलब्ध हैं,उन्होंने कहा कि इससे हजारों नवजात बच्चों की जान बचाई जा रही है।

भुगतान व्यवस्था हुई नियमित–मंत्री ने कहा कि अब अस्पतालों को समय पर भुगतान किया जा रहा है,पूरी प्रक्रिया डिजिटल एवं पारदर्शी बनाई गई है,निजी एवं सरकारी दोनों अस्पतालों का विश्वास बहाल हुआ है,उन्होंने दावा किया कि बेहतर क्रियान्वयन के कारण भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ को देश में प्रथम स्थान प्रदान किया।

अटल आरोग्य जांच योजना का विस्तार–मंत्री ने कहा कि किसी भी बीमारी का सही इलाज तभी संभव है जब समय पर उसकी सही जांच हो,इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने अटल आरोग्य जांच योजना का विस्तार किया, उन्होंने बताया कि जिला अस्पतालों,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों,प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया है, इस योजना के संचालन में एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका है।

जांच प्रणाली होगी और मजबूत–मंत्री ने कहा कि पहले कई जांचों के लिए नमूने दूसरे राज्यों की प्रयोगशालाओं में भेजने पड़ते थे, जिससे रिपोर्ट आने में विलंब होता था,अब इस व्यवस्था को बदलने के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनाई जा रही है।

96.68 करोड़ की इंटीग्रेटेड टेस्टिंग लैब–उन्होंने बताया कि लगभग 96 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है,इस प्रयोगशाला में दवाइयों की जांच,खाद्य पदार्थों की जांच,गुणवत्ता परीक्षण,आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षण एक ही परिसर में किए जा सकेंगे, उन्होंने कहा कि यह केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण सुविधा होगी।

दवाइयों की रिकॉर्ड जांच–स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में जितनी दवाइयों की जांच हुई है, उतनी शायद पहले कभी नहीं हुई,उन्होंने बताया बाजार से लगातार नमूने लिए जा रहे हैं, गुणवत्ता परीक्षण कराया जा रहा है, अमानक दवाइयों पर कार्रवाई की जा रही है, उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरत रही।

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष जोर...

मंत्री ने कहा कि केवल भवन निर्माण से स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं होती, उन्होंने कहा कि यदि अस्पताल में-प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स,आधुनिक उपकरण,स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं,नहीं हों तो अस्पताल का भवन केवल ढांचा बनकर रह जाता है, इसी सोच के तहत राज्य सरकार ने गुणवत्ता सुधार पर विशेष कार्य किया।

1297 स्वास्थ्य संस्थानों को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन...

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय विभिन्न मानकों के आधार पर अस्पतालों का मूल्यांकन करता है, इसी प्रक्रिया के अंतर्गत-1297 स्वास्थ्य संस्थानों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक का प्रमाणन प्राप्त हो चुका है, इनमें शामिल हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर,उप स्वास्थ्य केंद्र,प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल।

मिलावटी पनीर और खोवा पर लगातार कार्रवाई

मंत्री ने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग लगातार–नकली पनीर, मिलावटी खोवा, अमानक खाद्य पदार्थ,के खिलाफ अभियान चला रहा है,उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

डेयरी एनालॉग उत्पादों पर प्रतिबंध को बताया ऐतिहासिक निर्णय

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार ने ऐसे डेयरी एनालॉग एवं गैर-दुग्ध उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है जो उपभोक्ताओं को वास्तविक दूध उत्पाद होने का भ्रम पैदा करते हैं, उन्होंने कहा–उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जाएगा, मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ढाई साल का रिपोर्ट कार्ड : कैंसर से डायलिसिस तक,गुणवत्ता से आपातकालीन सेवाओं तक स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का दावा

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा-नक्सल प्रभावित बस्तर में घर-घर पहुंची स्वास्थ्य टीम, हजारों गंभीर मरीजों और हाई रिस्क गर्भवतियों की पहचान

अबूझमाड़ और चिंतागुफा जैसे क्षेत्रों को भी मिला गुणवत्ता प्रमाणन

मंत्री ने विशेष रूप से कहा कि यह उपलब्धि केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा—चिंतागुफा जैसे पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्र,ओरछा, कुटरू, अबूझमाड़ क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों को भी राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त हुआ है, उन्होंने कहा कि यह प्रमाण है कि स्वास्थ्य सेवाएं अब दुर्गम क्षेत्रों तक भी गुणवत्तापूर्ण रूप से पहुंच रही हैं।

618 और स्वास्थ्य संस्थान प्रमाणन की प्रक्रिया में...

मंत्री ने बताया कि 618 अन्य स्वास्थ्य संस्थान भी गुणवत्ता प्रमाणन की प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में प्रदेश के अधिकांश सरकारी अस्पताल राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को प्राप्त कर लेंगे।

आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ को देश में पहला स्थान...

प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना का विशेष उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि जब वर्तमान सरकार बनी तब निजी अस्पतालों का भुगतान लंबित था, लगभग 1700 करोड़ रुपये की देनदारी थी, कई निजी अस्पतालों ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद कर दिया था, सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए लंबित राशि का भुगतान शुरू किया।

जनस्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता

अपने संबोधन के इस हिस्से में मंत्री ने दोहराया कि स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य केवल अस्पताल चलाना नहीं,बल्कि एक ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जहां जांच समय पर हो,उपचार सुलभ हो,गरीब मरीज को आर्थिक परेशानी न हो, दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो, और हर नागरिक को सम्मानपूर्वक स्वास्थ्य सेवा मिले,उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को और ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए निरंतर कार्य करेगी।

विशेष रिपोर्ट (भाग-4) में पढ़िए

- पांच नए मेडिकल कॉलेजों को मिली मान्यता
- 14 नए नर्सिंग कॉलेज
- फिजियोथेरेपी कॉलेजों की स्थापना
- बिलासपुर और जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
- मेकाहारा के आधुनिकीकरण का खाका
- आयुष विभाग की उपलब्धियां
- सीजीएमएससी के निर्माण कार्य
- 700 बिस्तरीय अस्पताल
- कैंसर संस्थान
- क्रिटिकल केयर यूनिट
- विभाग की भविष्य की कार्ययोजना
- स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की प्रेस वार्ता का समग्र निष्कर्ष।

हाई कोर्ट ने लगाई राजस्व अफसरों को फटकार....'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' सीमांकन जैसे छोटे काम के लिए आम आदमी को हाई कोर्ट आना पड़ रहा है

बिलासपुर,03 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पहुंचे एक प्रकरण ने राज्य के राजस्व विभाग में व्याप्त भर्राशाही की पोल खोल कर रख दी है। आलम यह है कि यहां सीमांकन जैसे छोटे कम कोबपूरा करने में महीनों नहीं, सालों लगा दिए जाते हैं। हाई कोर्ट ने राजस्व विभाग की इस तरह की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने कहा कि नक्शा सुधार, नामांतरण और सीमांकन

जैसे छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी नागरिकों को विवश होकर हाई कोर्ट आना पड़ रहा है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतिहास कोर्ट ने 8 महीने से लंबित सीमांकन के मामले में तहसीलदार बिलासपुर को 60 दिन के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 'नक्शा सुधार, नामांतरण और सीमांकन जैसे राजस्व के छोटे-छोटे प्रकरणों के लिए आम आदमी को हाई कोर्ट में रिट दायर करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ' 'यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। इन मामलों का निराकरण स्थानीय स्तर पर ही हो जाना चाहिए। ' कोर्ट ने कहा कि राजस्व अफसर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, तभी लोगों को हाई कोर्ट आना पड़ रहा है।

बृजमोहन-आईएएस विवाद पर भूपेश बघेल का बड़ा हमला,सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

रायपुर,03 अगस्त 2026। रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल और स्वास्थ्य विभाग के सचिव आईएएस अमित कटारिया के बीच कथित बातचीत को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है। मामले ने प्रशासन और राजनीति दोनों में हलचल पैदा कर दी है। जानकारी के अनुसार, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्वास्थ्य सचिव के कथित आपत्तिजनक व्यवहार की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से की है। इस शिकायत के बाद लोकसभा सचिवालय भी पूरे मामले की जानकारी जुटा रहा है। विवाद के सामने आने के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।

भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर साधा निशाना : इस पूरे घटनाक्रम पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर राज्य सरकार का नहीं, बल्कि दिल्ली और नागपुर का प्रभाव दिखाई देता

है। बघेल ने कहा कि यदि किसी निर्वाचित सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय गरिमा के लिए उचित संकेत नहीं है। उन्होंने सरकार से प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग भी की।

जनप्रतिनिधि के सम्मान का मुद्दा उठाया : भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि राजनीतिक या वैचारिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का सम्मान लोकतंत्र की मूल भावना का हिस्सा है। उन्होंने लिखा कि बृजमोहन अग्रवाल देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था लोकसभा के सदस्य हैं और रायपुर की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उनके साथ कथित रूप से असम्मानजनक व्यवहार करना केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उन सभी मतदाताओं का भी अपमान है जिन्होंने उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुना है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने बयान में यह भी कहा कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर स्थानीय सरकार की बजाय दिल्ली और नागपुर का प्रभाव अधिक दिखाई देता है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह*(पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)